

इंदौर, गुरुवार 29 जनवरी 2026

वर्ष : 5 अंक : 80

पृष्ठ : 6 मूल्य : 2

dainikindoresanket.com

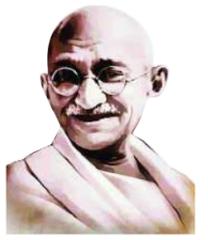
dainikindoresanket

dainikindoresanket

dainikindoresanket24@gmail.com

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत



राष्ट्रपिताको नमन...

अंदर के पन्नों पर...

वीआरटीएस तोड़ने के लिए दो पैकेज में टेंडर



पेज-2

फिटनेस को लेकर गंभीर हैं अक्षरा सिंह



पेज-5

चुनावी राज्यों में दिखेगा मप्र के नेताओं का दम



पेज-6

न्यूज ब्रीफ

- पंजाब-हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी
- बारामती: काटेवाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार को दी गई अंतिम विदाई
- जमीन के बदले नौकरी: लालू यादव से जुड़े मामले पर दिल्ली कोर्ट में आज होगी सुनवाई
- वेनेजुएला को एक जब्त किया हुआ तेल टैंकर वापस करेगा अमेरिका
- गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिन के दौरे पर असम पहुंचेंगे
- फेडरल रिजर्व ने ट्रप के राजनीतिक दबाव को नजरअंदाज करते हुए ब्याज दरें स्थिर रखीं
- सोनम वांगचुक की पत्नी से जुड़ी अजीब पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वे पेश करेंगे
- चांदी ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड; बार लाख के पार
- शेयर बाजार में गिरावट; संसेक्स 248 अंक फिसला, निफ्टी 25300 पर खुला

प्रदेश में शीतलहर के प्रकोप से कांपा शहर

पचमढ़ी सबसे ठंडा, 20 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा, इंदौर-भोपाल में सुबह 10 बजे तक नहीं निकली धूप

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल • ओले और बारिश का दौर थमने के बाद मध्य प्रदेश में सर्दी और घने कोहरे का असर बढ़ गया है। गुरुवार सुबह प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरा छाया रहा। कई जिलों में सुबह 10 बजे तक धूप नहीं निकली। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 20 से ज्यादा जिलों में मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और विजिबिलिटी कम रही।

मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर और दतिया में सबसे घना कोहरा रहा। रात के तापमान में भी गिरावट आई है। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम

30 जनवरी- प्रदेश के उत्तरी हिस्से में कोहरा छा सकता है। बारिश का अलट नहीं है। दिन-रात में ठंड का

असर बढ़ सकता है। 31 जनवरी- ग्वालियर, भिंड, सूरना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा,

राजगढ़ और शाजापुर में भी कोहरा छा सकता है। 1 फरवरी- भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, हरदा, सीहोर, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, गुना, अशोकनगर,

शिवपुरी, श्योपुर, सूरना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, सागर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा में भी कोहरा छा सकता है।

इंदौर में चल रही सर्द हवाएं

इंदौर में आज भले ही कोहरे का असर बहुत कम नजर आया, लेकिन मौसम काफी ठंडा बना हुआ है। सुबह से ही तेज सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे ठंडुरन बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के कारण लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई दिए और सुबह-शाम घर से बाहर निकलने में परेशानी महसूस की गई। मौसम में आई इस ठंडक का असर जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सर्द हवाओं के चलते बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही

अपेक्षाकृत कम रही।

ग्वालियर में बारिश के बाद बढ़ी ठंड

ग्वालियर में दो दिन से हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। शीत लहर के असर से ठंडक बढ़ गई है और शहर रात भर घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। सुबह के समय दृश्यता कम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण रात के तापमान में करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस का अंतर दर्ज किया गया है। मौसम में आए इस बदलाव से ठंड और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं।

वरिष्ठों के पुनर्वास की तैयारी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल • मप्र में लंबे समय से प्रतीक्षित निगम-मंडलों और विकास प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब सभी नियुक्तियों एक साथ करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद अब अलग-अलग सूचियों के बजाय एक ही जंबो लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें करीब 35 नेताओं को जगह मिल सकती है। इससे पहले प्रदेश नेतृत्व की योजना विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल जैसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों में पहले चरण में नियुक्तियों करने की थी। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव और केंद्रीय व्यस्तताओं के कारण मामला टलता रहा। पुनर्वास की रैस में सबसे बड़ा नाम प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का है। माना जा रहा है कि भार्गव के अनुभव और वरिष्ठता को देखते हुए सरकार उन्हें कोई बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी संवैधानिक या राजनीतिक जिम्मेदारी सौंप सकती है। उनके अलावा पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पन्ना से पांच बार के विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, हरिशंकर खटीक, अजय विश्वासी और अर्चना चिटनीस जैसे कदमचोर नेताओं को भी महत्वपूर्ण निगम-मंडलों की कमान सौंपी जा सकती है। जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश में निगम-मंडलों और विभिन्न प्राधिकरणों में लंबित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अब भाजपा ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी पहले इन नियुक्तियों को चरणबद्ध तरीके से करने की तैयारी में थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद अब सभी दर्जा प्राप्त



मंत्रियों और प्रमुख पदों की सूची एक साथ जारी करने का निर्णय लिया गया है। माना जा रहा है कि यह नियुक्तियों विधानसभा के बजट सत्र से पहले घोषित की जा सकती है। सरकार और संगठन पिछले करीब चार महीनों से राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी में जुटा है। संगठन और सरकार स्तर पर कई दौर की चर्चा के बाद सूची को मालाभूग अंतिम रूप भी दे दिया गया था, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। पहले योजना थी कि पहली किस्त में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों जैसे विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जाए।

35 नेताओं का होगा पुनर्वास

जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश के साथ प्रदेश नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। इसी बैठक में राजनीतिक नियुक्तियों की अंतिम सूची पर मुहर लग सकती है। संगठन सूत्रों का कहना है कि इस सूची में करीब 35 नेताओं को विभिन्न निगम-मंडलों, आयोगों और प्राधिकरणों में जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल, विधानसभा चुनाव 2023 के बाद से ही निगम-मंडलों में नियुक्तियों को लेकर संगठन पर दबाव बना हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव के

बाद नियुक्तियों करने की योजना थी, लेकिन भाजपा के संगठन चुनाव, फिर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी के चलते मामला आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद बिहार चुनाव के चलते भी निर्णय टलता रहा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही वरिष्ठ नेताओं को भरोसे में लिया है। वे उपेक्षित और घर बैठ चुके वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस बार की नियुक्तियों में पार्टी का खास फोकस पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों के पुनर्वास पर है। ऐसे कई नेता हैं, जो चुनाव के बाद संगठन या सरकार में किसी जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इनमें से कई नेताओं के पास फिलहाल कोई सक्रिय दायित्व नहीं है, जिसे देखते हुए पार्टी उन्हें निगम-मंडलों और आयोगों में समायोजित करना चाहती है। पूर्व मंत्री जयंत मलैया को छठवें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाने की संभावना बताई जा रही है। वे पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, इसलिए इस पद के लिए उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इसी तरह ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जो पांच बार विधायक और दो बार मंत्री रह चुके हैं, तथा हरिशंकर खटीक, जो चार बार विधायक रहने के साथ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष और संगठन में कई दायित्व निभा चुके हैं, भी सूची में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अजय विश्वासी, अर्चना चिटनीस, दीपक सक्सेना जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम भी पुनर्वास की दौड़ में बताए जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि नियुक्तियों में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। कांग्रेस से भाजपा में आए छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से विधायक कमलेश शाह भी किसी अहम पद की प्रतीक्षा में हैं।

एसआईआर ने दोनों पार्टियों को पशोपेश में डाला

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल • एसआईआर (स्पेशल इंटीग्रेटेड रिजीन) के बाद जारी किए गए मतदाताओं के आंकड़ों ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को पशोपेश में डाल दिया है। दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेट्री ने निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर कार्यक्रम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नाम पर आम मतदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका बन गई है। वहीं भाजपा ने भी आयोग के सामने अपनी बात रखी है।

कांग्रेस अब दस्तावेजों के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करने जा रही है। पार्टी ने हर जिले से रिपोर्ट मांगी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार नाम काटने वाले फॉर्म सात में भारी अनियमितता के आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि प्रिंटेड फॉर्म लिए गए, जो नहीं लिए जा सकते थे। उधर, भाजपा ने स्थायी रूप से स्थानांतरित 22 लाख से अधिक मतदाताओं को अक्सर न देने और 20 लाख लोगों के नाम न जुड़ पाने का मुद्दा उठाते हुए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा को ज्ञापन दिया है। प्रदेश में एसआईआरके अंतर्गत गणना पत्रक जमा कराने के साथ दावा-आपत्ति का चरण पूरा हो चुका है। अब इनका निराकरण किया जाएगा और फिर 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू प्रत्यूरी को आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई है। जो नाम काटे गए, उनमें से कई के दोबारा आवेदन जमा कराए गए हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन अधिकारियों पर दबाव बनाकर प्रिंटेड फॉर्म जमा किए हैं, जबकि ऐसा करने पर



31 लाख मतदाताओं को लेकर आपत्ति

उधर, प्रदेश भाजपा ने भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि 31 लाख मतदाताओं के नाम अनुपस्थित और स्थायी रूप से स्थानांतरित की श्रेणी में डालकर प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए गए। किसी को भी अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला। इनमें से कई मतदाता उपलब्ध हैं और इन्हें फिर से नाम जुड़वाने के लिए प्रक्रिया करनी पड़ रही है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 लाख मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाए। प्रक्रियात्मक त्रुटि के नाम पर भी मतदाताओं को नोटिस दिए गए हैं, जिससे वे परेशान हो रहे हैं। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि हमारे बूथ लेवल एजेंटों ने नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कराए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी नागांव (असम) ने गलत फॉर्म-सात के आधार पर की जा रही समस्त प्रक्रिया को निरस्त किया है। रायसेन सहित अन्य जिले में एक ही व्यक्ति ने 200-200 आपत्तियां दर्ज कराईं। एक-एक व्यक्ति ने डेढ़-डेढ़ सौ फॉर्म जमा किए हैं, जबकि एक दिन में एक बूथ लेवल कार्यकर्ता 15 फॉर्म जमा कर सकता है। उन मतदाताओं को भी त्रुटि के नाम पर नोटिस दिए गए हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जानकारी गणना पत्रक में दी थी। कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामले का कहना है कि सभी जिला मुख्यालयों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

निर्देश

प्रदेश के साढ़े चार लाख शासकीय सेवकों को मिलेगा लाभ

प्रदेश में अब 65 साल में सेवानिवृत्त होंगे कर्मचारी

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल • प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार राज्य के करीब साढ़े चार लाख से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। प्रदेश में शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने की कवायद शुरू हो गई है। संभवतः लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु-सीमा में एकरूपता लागू हो सकती है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मप्र संकल्प पत्र-2023 को पूरा करने की पहल शुरू की। जिस सामान्य प्रशासन विभाग पूरा करने में प्राथमिकता के साथ जुट गया है।

विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र-2023 में मप्र के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एकरूपता लाने का विषय शामिल था। साथ ही



6 साल बाद बढ़ने जा रही है आयु सीमा

प्रदेश में मई 2018 तक शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल थी। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जून 2018 से इसे बढ़ाकर 62 कर दिया। अब 6 साल बाद फिर से सरकार सेवानिवृत्ति की सीमा 62 से बढ़ाकर 65 करने जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि इससे सरकार को कर्मचारियों की हो रही कमी से फौरी राहत मिलेगी। साथ ही वित्त स्थिति ठीक नहीं होने से सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान की राशि भी नहीं देनी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री को विभिन्न कर्मचारी संगठन, मप्र राज्य कर्मचारी कल्याण समिति की ओर से भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर मांग की गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन

यादव ने भी शपथ लेने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में संकल्प पत्र 2023 में शासकीय सेवकों से जुड़े मसलों को पूरा करने के निर्देश दे दिए थे।

वित्त विभाग पर पड़ेगा असर

सरकार के उच्च सूत्रों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल करने का फैसला शासन स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संकल्प पत्र 2023 को लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले करने के पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पहल की। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 साल करने पर खजाने पर पड़ने वाले भार को लेकर वित्त विभाग से अभिमत मांगा है। वित्त से अभिमत आने के तत्काल पर सेवानिवृत्ति में एकरूपता के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जा सकता है। यह बता दें कि अभी तक प्राध्यापक, चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं अन्य सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 साल है। अब सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल करने की तैयारी है।

अपर आयुक्त के आदेश से इंदौर प्रशासन के हाथ से फिसली क्रिश्चियन कॉलेज की जमीन

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • क्रिश्चियन कॉलेज की 500 करोड़ की जमीन पर विवाद बढ़ गया है। आईएएस अपर आयुक्त तरुण भटनागर के आदेश के चलते हाईकोर्ट से स्टे हो गया। छह सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।

जिस बात की आशंका थी वही हुआ। इंदौर संभागायुक्त कार्यालय में पदस्थ 2012 बैच के आईएएस अपर आयुक्त तरुण भटनागर के आदेश से खेला हो गया। इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज की 500 करोड़ की जमीन पर कलेक्टर कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट से स्टे हो गया है।

याचिकाकर्ता क्रिश्चियन कॉलेज के अधिवक्ता ने कहा कि यह आदेश कलेक्टर कोर्ट में 23 जनवरी के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन आदेश 12 जनवरी को ही कर दिया गया। इसकी वजह थी कि 19 जनवरी को अपर आयुक्त में हमारी तरफ से प्रति परीक्षण



का आवेदन लगाया था। इसमें अपर आयुक्त कोर्ट से यथास्थिति के आदेश हुए थे। इसी आदेश को विफल करने के लिए ही इस तय तारीख से पहले कलेक्टर कोर्ट से 12 जनवरी को आदेश कर दिया गया। इस बात को हाईकोर्ट इंदौर ने मान्य किया और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि 19 जनवरी को अपर आयुक्त कोर्ट से यथास्थिति के आदेश थे। कलेक्टर कोर्ट से 23 जनवरी को आदेश होना था, लेकिन यह 12 जनवरी को हो गए। ऐसे में आदेश दिए जाते हैं कि 12 जनवरी के कलेक्टर कोर्ट

के आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा। छह सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी। इस आदेश के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम तीन महीने से मेहनत कर रही थी और इसमें हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक से जीत कर आई थी, लेकिन अपर आयुक्त के एक आदेश ने पूरी 500 करोड़ की जमीन सरकार के हाथ से निकाल दी। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की कोर्ट में क्रिश्चियन कॉलेज की जमीन को सरकारी घोषित करने का राजस्व संहिता की धारा 181 व 182 का केस चल रहा था।

न्यूज ब्रीफ

369 नए सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बच्चे राष्ट्र की पूंजी हैं। इनका भविष्य संवारना हम सबको जिम्मेदारी है। बेहतर शिक्षा के लिए मजबूत अधोसंरचनाओं और कुशल मानव प्रबंधन पर हम प्रदेश के बच्चों का भविष्य बेहतर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा मूल संकल्प है कि प्रदेश के स्कूल जाने योग्य हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो। इसी संकल्प की पूर्ति के लिए हमने प्रदेश में गुरुकुल शिक्षा पद्धति से प्रेरणा लेकर अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सांदीपनि विद्यालयों की शुरुआत की है। अब तक प्रदेश में 369 नए सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सबको अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। इस अधिनियम के अंतर्गत हमने अब तक प्रदेश के 8.50 लाख से अधिक विद्यार्थियों की समुचित शिक्षा के लिए सभी स्थायी प्रबंध और पुख्ता शिक्षण व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दिए हैं। बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए हम कोई कमी नहीं करेंगे।

पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. बी. डी. श्रीवास्तव के निर्देशन में ईको क्लब एवं प्राणी शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. पूजा जैन द्वारा 'पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, पर्यावरण विभाग राज्य शासन भोपाल, वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली' द्वारा प्रायोजित 'बीज संग्रहण परियोजना एवं सीड बैंक' की प्रदर्शनी का आयोजन गत दिवस किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वनस्पति शास्त्र विभाग के सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉ. सुभाष सोनी ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्राओं द्वारा की गई इस पहल को सराहा एवं सीड आइडेंटिफिकेशन के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया।

उज्वल भविष्य की ओर एक सशक्त कदम

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. बी. डी. श्रीवास्तव के संरक्षण, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. पी. पी. बैरागी के मार्गदर्शन में 'स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन गाइडेंस' के अंतर्गत करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. सीमा तिवारी द्वारा 'रोजगार, उद्यमिता विकास अवसर एवं आनंद मेले का आयोजन' किया गया। यह रोजगार मेला 800 से अधिक छात्राओं को शिक्षा से रोजगार, योग्यता से अवसर और आत्मनिर्भरता से नेतृत्व की दिशा में जोड़ने के लिए सशक्त प्रयास है। इस आयोजन का उद्देश्य छात्राओं को रोजगार के विभिन्न अवसरों, उद्यमिता विकास योजनाओं तथा स्वरोजगार की संभावनाओं से अवगत कराना था।

अमानक स्तर, मिलावट तथा मिथ्या छाप सामग्री पर कार्रवाई सख्त कार्रवाई : 13 मिलावटखोरों पर लगा 21 लाख का जुर्माना

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार के सख्त रुख के तहत इंदौर जिले में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत प्रशासन ने मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। इसी क्रम में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी नवजीवन विजय पवार द्वारा बुधवार को की गई कार्रवाई में 13 मिलावटखोरों के विरुद्ध 21

लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई। किसी भी दशा में नहीं छोड़ेंगे कलेक्टर ने कहा है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सुरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और मिलावट करने वालों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आम नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले



में चलाए गए अभियान के तहत जिले में विभिन्न प्रतिष्ठानों से लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सोंफ, पनीर, घी, पेड़ा मिठाई, हॉग चना, मिल्क पाउडर आदि के नमूने लिए गए थे। जांच उपरत इन

इन संस्थानों पर की गई कार्रवाई

इसी प्रकार मेसर्स यू एंड मी इंटरप्राइजेस पर एक लाख, मेसर्स सनी इंटरप्राइजेस पर 2 लाख 50 हजार, मेसर्स वैजबीटस रेस्टोरेंट प्रा. लि. पर एक लाख रुपए, मेसर्स जय मां अम्बे दूध भण्डार एवं स्वीट्स पर एक लाख, मेसर्स चिक एन सर्व पर 50 हजार, मेसर्स श्री राधे स्वीट्स एंड नमकीन पर एक लाख, मेसर्स अरिहंत मिल्क प्रोडक्ट्स पर 2 लाख 50 हजार, मेसर्स अग्रवाल स्नेक्स फूड इंडिया इंडिया पर एक लाख, मेसर्स एस एंड एन श्रौफल कन्फेक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख 50 हजार और मेसर्स विश्वकर्मा गृह उद्योग पर 2 लाख रुपए शामिल हैं। इस तरह कुल 13 मिलावटखोरों पर 21 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

नमूनों में अमानक स्तर, मिलावट तथा मिथ्या छाप सामग्री, अस्वच्छ वातावरण का होना प्राया गया। जिन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनमें मेसर्स रिया स्वीट्स एंड लघु उद्योग पर 3 लाख, मेसर्स मोहनलाल प्रह्लाद दास एंड संस पर 1 लाख 50 हजार, मेसर्स गुलक ट्रेड लिंक पर 1 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

कार्यवाही नहीं : अभी भी लगेंगे जांच की रिपोर्ट आने में चार दिन

विविध के आईटी में रैगिंग का मामला



दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आईटी में रैगिंग का मामला सामने आने के बाद अभी तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। डी होस्टल में रहने वाले बीटेक फर्स्ट इयर के छात्र को शिकायत के बाद सेकंड इयर के छात्रों के खिलाफ जांच प्रक्रिया चल रही है। बुधवार को प्रबंधन ने बताया अभी तक छात्रों पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। जांच की रिपोर्ट आने में तीन से चार दिन लगेंगे। सूत्रों को माने तो फर्स्ट इयर के छात्रों ने आरोप लगाया कि सीनियर्स जबरन

सिगरेट पीने के लिए मजबूर करते हैं। मना करने पर उन्हें बैच आउट करने (शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों से अलग रखने) की धमकी देते हैं। शिकायत में यह भी सामने आया है कि इस तरह की हरकतों में कुछ फर्स्ट इयर के छात्र भी शामिल हैं। शुरुआत में केवल एक छात्र ने फोन के माध्यम से प्रबंधन को इस स्थिति की जानकारी दी थी। जब संस्थान ने सख्ती दिखाई और सभी जूनियर छात्रों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की, तो लगभग 7 से 8 छात्रों ने अपने साथ हुई रैगिंग की पुष्टि की।

एलआईजी से नवलखा एलिवेटेड कॉरिडोर पर आज बड़ा फैसला

रूट, लंबाई और बदलाव पर चर्चा, निकलेगा ट्रैफिक की समस्या का सामधान

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • बीआरटीएस हटने के बाद एलआईजी से नोलखा चौराहा तक प्रस्तावित 5.5 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी, सांसद और सभी विधायक शामिल होंगे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉरिडोर की पूरी योजना प्रस्तुत करेंगे।

यह कॉरिडोर एलआईजी चौराहा, पलासिया, गीता भवन, शिवाजी वाटिका, जीपीओ, इंदिरा गांधी प्रतिमा होते हुए नौलखा चौराहा तक जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण का निर्णय पहले ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लिया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग ने योजना बनाकर इसकी स्वीकृति भी ले ली थी, जिसके आधार पर निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य एक गुजरात की एंजेंसी को सौंपा गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर की सारी प्लानिंग हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा और मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक 15 फरवरी से पहले काम शुरू

कर देंगे। संबंधित एंजेंसी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी चर्चा हो चुकी है। दरअसल, 14 दिसंबर को ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर विकास को लेकर हुई बैठक में एलिवेटेड कॉरिडोर का मुद्दा सामने आया था। बैठक में मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए निर्देश दिए थे कि जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर कॉरिडोर की लंबाई और स्वरूप तय किया जाए। पूर्व में स्वीकृत योजना के अनुसार यह एलिवेटेड कॉरिडोर छोटी खजुरानी से नोलखा चौराहा तक बनाया जाना है। प्रस्तावित मार्ग तीन प्रमुख चौराहों- गीता भवन चौराहा, गीता भवन चौराहा और व्हाइट चर्च चौराहा-से होकर गुजरेगा। आज होने वाली बैठक में जनप्रतिनिधियों की सहमति से कॉरिडोर की लंबाई और अन्य बिंदुओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि किसी प्रकार के संशोधन का सुझाव आता है, तो उस पर भी इसी बैठक में चर्चा कर फैसला किया जाएगा। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सहित लोक निर्माण विभाग, प्रशासन और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

इंदौर उद्यान समिति ने उठाया रोटरी का मुद्दा-इंदौर उद्यान समिति ने एबी रोड पर फ्लाईओवर के बजाय रोटरी आधारित एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव दिया था। समिति ने अन्य शहरों का दौरा कर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रेजेंटेशन भी दिखाया। समिति के अजित नारंग के अनुसार, एबी रोड पर 5.9 किमी क्षेत्र में लगभग 63 प्रतिशत हिस्से में फ्लाईओवर प्रस्तावित थे। ऐसे में पूरे 100 प्रतिशत हिस्से में एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर चौराहों पर रोटरी और रैम्प (भुजाएं) उतारने से यातायात अधिक सुगम हो सकता है। **अगले माह से कॉरिडोर के फाउंडेशन का काम होगा**-टेकेदार एंजेंसी ने साइट पर आरएमसी प्लांट, कैप और साइट ऑफिस स्थापित कर दिया है। फरवरी 2026 से फाउंडेशन का काम शुरू किया जाएगा। वर्तमान में इस रोड पर 9 प्रमुख इंटरसेक्शन हैं, जहां पीक आवर्स में ट्रैफिक दबाव 6500 पीसीपी (पैसेंजर कार यूनिट) प्रति घंटे तक रहता है। कॉरिडोर पर तीन प्रमुख भुजाएं उतरेंगी। पहले चरण में एलआईजी से शिवाजी वाटिका के बीच काम शुरू होगा।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव-अध्यक्ष मनीष यादव व सचिव मनीष गडकर बने

23 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया मतदाताओं ने

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव बुधवार को संपन्न हुए, जिसमें 23 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के लिए 1914 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देर रात आए चुनाव नतीजों में अध्यक्ष पद पर मनीष यादव, उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक तुगनावत, सचिव मनीष गडकर और ज्वाइन सेक्रेटरी अमित राज चुने गए। इसी तरह कार्यकारिणी सदस्यों में राहुल पंचाल, तेजस जैन, अमन मालवीय, रमेशचंद्र सूर्यवंशी तथा अनिक जैन चुने गए। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। चुनाव में 23 उम्मीदवार अलग-अलग पदों पर अपनी किस्मत आजमाते नजर आए। मतदान सुबह 11 बजे शुरू हुआ और शाम छह बजे तक चला। इसके बाद मतगणना शुरू हुई। चौथे राउंड तक अध्यक्ष और सचिव पद के उम्मीदवारों के बीच कशमकश चलती रही। हाईकोर्ट एसोसिएशन के चुनाव में 2632 सदस्यों को वोट डालने की पात्रता थी, लेकिन वोट देने के लिए 1914 वोटर ही आए। इनमें मेयर पुष्पमित्र भार्गव व उनकी पत्नी जूही



भार्गव भी थे। दोनों मतदान करने आए थे। सबसे ज्यादा उम्मीदवार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए थे। दोनों पदों पर पांच-पांच उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इस कारण वोट भी बंट गए और मुकाबला कांटे का हो गया। सुबह बजे वोटिंग शुरू हुई। सुबह अच्छी वोटिंग हुई और कतार भी नजर आई। 11 दोपहर में भीड़ कम रही। अध्यक्ष पद पर गौरव श्रीवास्तव और जीपी सिंह और मनीष यादव के बीच टक्कर रही। नवे राउंड तक सिंह को 212 और यादव को 261 और श्रीवास्तव को 270 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक तुगनावत ने पहले राउंड से बढ़त बनाई, जो नवे राउंड तक जारी रही।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे कड़ा मुकाबला रहा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज द्विवेदी एवं मॉडिया प्रभारी अजय मिश्रा ने बताया कि बुधवार शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। देर रात परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सबसे कड़ा मुकाबला रहा। नवे राउंड तक उन्हें 442 वोट मिल चुके थे, सचिव पद पर भी मनीष गडकर और गोविंद राय के बीच टक्कर रही। सहसचिव पद पर नवे राउंड तक अमित राय को 455 और ज्ञानेंद्र शर्मा को 430 वोट मिले थे।

ट्रेजर आइलैंड मॉल में मनाया दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम



दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • इंदौर ट्रेजर आइलैंड मॉल ने डीपीएस स्कूल के सहयोग से गणतंत्र दिवस के अवसर पर दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस आयोजन में कला, संगीत और सामुदायिक भागीदारी का संगम देखने को मिला। डीपीएस स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता और देशभक्ति को कला और संगीत प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाया। कार्यक्रम की शुरुआत 25 जनवरी को एक कला प्रदर्शनी से हुई, जिसमें छात्रों द्वारा बनाई गई 60 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। इस प्रदर्शनी को अच्छा प्रतिसाद मिला और लगभग 130 छात्र एवं उनके परिवारजन मौल पहुंचे। कलाकृतियों में देशभक्ति, एकता और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली, जिसे मॉल में आए आगंतुकों ने सराहा।

स्कूल का गौरव

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का आयोजन नेहरू स्टेडियम में हुआ जिसमें प्रेसीडेंसी हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट पुलिस कैडेट छात्राओं को गणतंत्र दिवस समारोह - 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजेश सिंह, एसीपी श्रीमती अपूर्वा किलेदार, रक्षित निरीक्षक दीपक पाटिल व सब इंस्पेक्टर शिवम ठक्कर उपस्थित रहे। ए.एस.आई.ग्येदर यादव की सिखलाई ने एसपीसी कैडेट को इस मुकाम तक पहुंचाया। प्रेसीडेंसी स्कूल प्राचार्य राधेश्याम जामले ने छात्राओं को शुभकामनाएं दीं।

बीआरटीएस तोड़ने के लिए दो पैकेज में टेंडर टेकेदार नहीं मिले तो निगम खुद करेगा काम

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • बीआरटीएस की रैलिंग और बस स्टॉप नगर निगम के लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं। कोर्ट की लगातार फटकार के बाद अब नगर निगम ने बीआरटीएस के बस स्टॉप और रैलिंग तोड़ने के लिए दो अलग-अलग पैकेज में टेंडर जारी किए हैं। निगम को इस प्रक्रिया से डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की आय होने की उम्मीद है। यदि किसी टेकेदार को ओर से रुचि नहीं दिखाई जाती है तो नगर निगम खुद इस कार्य को अंजाम देगा। **डेढ़ करोड़ से अधिक की आय की संभावना**-नगर निगम अधिकारियों के अनुसार



बीआरटीएस के ढांचे को हटाने से निगम को अच्छी खासी आय हो सकती है। इसके लिए निरंजनपुर से लेकर राजीव गांधी प्रतिमा तक की रैलिंग और बस स्टॉप को तोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस पूरे कार्य से निगम को करीब डेढ़ करोड़ रुपये

से अधिक की आमदनी होने का अनुमान है। **पहले ही ठेकेदार छोड़ चुका है काम**-इससे पहले भी नगर निगम ने बीआरटीएस की रैलिंग तोड़ने का कार्य एक ठेकेदार को सौंपा था, लेकिन ठेकेदार अधूरा काम

छोड़कर फरार हो गया। मामले में लापरवाही और देरी को लेकर कोर्ट ने भी नगर निगम अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। **60 दिन में काम पूरा करने की शर्त**-जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठी ने बताया कि जो भी फर्म यह ठेका लेगी, उसे 60 दिन के भीतर पूरा काम करना होगा। यदि टेंडर प्रक्रिया में कोई भी ठेकेदार सामने नहीं आता है, तो नगर निगम अपने संसाधनों से यह कार्य शुरू करेगा। स्टेडियम क्षेत्र में पहले भी निगम ने इसी तरह अपने स्तर पर बस स्टॉप तोड़ने का काम कराया था।

एक साल में बनेगा सत्यसाई चौराहे का फ्लायओवर, सौ साल तक मजबूत रहेगा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • सत्यसाई चौराहे पर बन रहे फ्लायओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को गति देने के लिए प्रशासन और निर्माण एंजेंसी लगातार सख्त कदम उठा रही है। इसी क्रम में हाल ही में एक होटल और उसके पास बने महिला सुविधा घर को तोड़ दिया गया है। इससे पहले इसी मार्ग पर बड़ी संख्या में पेड़ों को कटाई भी की जा चुकी है। अभी यहां पर दिनरात काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि एक साल में इस ब्रिज को तैयार करके शुरू कर दिया जाएगा। ब्रिज को बना रहे इंजीनियर्स का कहना है कि इसकी इंजीनियरिंग में आधुनिक

तकनीकों का उपयोग करके इसे बेहद मजबूती के साथ बनाया जा रहा है। अगले 100 साल तक यह हैवी ट्रैफिक लोड उठाने में सक्षम रहेगा। ध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सत्यसाई चौराहे पर फ्लायओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार हाल ही में सर्विस रोड पर बने होटल और महिला सुविधा घर के कारण निर्माण कार्य में परेशानी आ रही थी। इन्होंने बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की गई। हाल ही में कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल ने शहर में बन रहे चार फ्लायओवर

ब्रिज का संयुक्त निरीक्षण किया था। इसमें निरंजनपुर, सत्यसाई चौराहा, मूसाखेड़ी चौराहा और आईटी पार्क चौराहा शामिल थे। निरीक्षण के दौरान निर्माण एंजेंसियों से कार्य में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली गई और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए गए। सत्यसाई चौराहे पर फ्लायओवर ब्रिज को आकार देने के लिए इससे पहले ही करीब 150 पेड़ों को कटाई भी की जा चुकी है। यह कटाई भी रात के समय की गई थी, जिसको लेकर पहले ही सवाल उठ चुके हैं। अब होटल और सुविधा घर तोड़े जाने के बाद एक बार फिर इस परियोजना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

न्यूज ब्रीफ

श्री श्रीविद्याधाम के 31वें प्रकाशोत्सव पर 3100 दीपों से किया गया मनोहारी श्रृंगार

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • विमानतल मार्ग स्थित श्री श्रीविद्याधाम आश्रम के 31वें प्रकाशोत्सव का समापन महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के पावन सांनिध्य में आज विद्वानों द्वारा मां ललिता महात्रिपुर सुंदरी भगवती को 56 भोग समर्पण एवं दीपोत्सव के साथ हुआ। आश्रम परिवार के सुरेश शाह, पं. दिनेश शर्मा, राजेन्द्र महाजन ने बताया कि इस अवसर पर मंगलवार शाम को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आचार्य पं. राजेश शर्मा एवं अन्य 31 विद्वानों की मौजूदगी में समूचे परिसर को 3100 दीपों से श्रृंगारित किया, जिसकी आभा आज सुबह तक दमकती रही। माँ पराम्बा के गर्भगृह सहित आश्रम स्थित सभी देवाल्यों में आज भी आकर्षक दीपोत्सव मनाया गया। इस मनोहारी छटा के दर्शन के लिए मंदिर पर भक्तों का सैलाब देर रात से लेकर आज आज दिनभर बना रहा। प्रसाद वितरण के साथ समापन हुआ।

साजन नगर खाटू श्याम मंदिर पर आज शाम पीताम्बर परिधान का निशुल्क वितरण

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • नवलखा, साजन नगर स्थित खाटू श्याम पर गुरुवार 29 जनवरी को जया एकादशी के उपलक्ष्य में आम श्याम भक्तों को संध्या 7 बजे से श्याम बाबा की दिव्य ज्योति, भव्य श्रंगार एवं कीर्तन के दर्शनों के बीच पीताम्बरी वस्त्र (परिधान) बागा का निशुल्क वितरण किया जाएगा। मंदिर समिति के सुरेश रामपीपलिया एवं रहवासी संघ के अध्यक्ष सुजीत शर्मा ने बताया कि समाजसेवी अशोक अग्रवाल मारवाड़ी एवं नेहा गर्ग के सहयोग से गुरुवार को दिव्य ज्योति के दर्शन एवं भजन संकीर्तन के बीच भक्तों को पीताम्बरी वस्त्र (परिधान) बागा का वितरण किया जाएगा। बागा खाटू बाबा का वह परिधान है जो वर्ष में केवल एक बार वस्त्रतं पंचमी पर बाबा को धारण कराया जाता है। बाबा पूरे वर्ष यह वस्त्र धारण करते हैं और मान्यता है कि यह पवित्र और चमत्कारिक परिधान घर में रखने या भक्त द्वारा धारण करने से घर की अनेक समस्याओं से मुक्ति तो मिलती ही है, निःसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति, निर्धनों को धन और बीमारों को स्वास्थ्य लाभ सहित सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है।

योग शिविर में साधकों ने लिया 'स्वस्थ राष्ट्र-समृद्ध राष्ट्र' का संकल्प

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन एवं चमेली देवी योग केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में गीता भवन में चल रहे योग शिविर में साधकों ने पूरे जोश एवं उत्साह के साथ तिरंगा राष्ट्रध्वज लहराते हुए वन्दे मातरम के सामूहिक गान एवं भारत माता के जयघोष के बीच गणतंत्र दिवस मनाया। समाजसेवी प्रेमचंद गोयल एवं शिविर संयोजक किशोर गोयल ने राष्ट्र ध्वज फहराया और सभी साधकों को देश के 77 वें गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं समर्पित की। इस मौके पर गीता भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष राम एरन एवं मंत्री रामविलास राठी ने साधकों को योग के माध्यम से स्वस्थ राष्ट्र-समृद्ध राष्ट्र का संकल्प दिलाया।

अग्रसेन महासभ के सामूहिक विवाह समारोह के लिए समितियां गठित

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • श्री अग्रसेन महासभा द्वारा 13-14 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में विभिन्न समितियों का गठन किया गया। सामूहिक विवाह के लिए सभी तैयारियां 'घर जैसी शादी' की तरह की जा रही है। महासभा परिवार की महिलाएं और नवयुगलों

क्या मंत्री पद छोड़कर केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे विजयवर्गीय ?

भोपाल (एजेसी) • कैलाश विजयवर्गीय मंत्री पद छोड़ेंगे। चोंकिए नहीं हम आपको कोई इनफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। हम आपको भविष्य की संभावना बता रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। बल्कि बीजेपी का ये नेता अपने हालिया पद से ज्यादा बड़े पद और ज्यादा बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। क्योंकि पार्टी अब उन्हें ऐसी जिम्मेदारी सौंप सकती है जो उनके तजुबे के अनुसार हों। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं प्रदेश के कुछ और नेताओं के दिन भी फिर सकते हैं। आप पिछले कई समय से ऐसी खबरें पढ़ या सुन रहे होंगे कि मध्यप्रदेश के मुखिया मोहन यादव और सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच खटपट जारी है। इस खटपट के बीच खबर आ रही है कि कैलाश विजयवर्गीय एक और बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि, वो उस जिम्मेदारी के साथ मंत्री पद पर न रहेंगे या नहीं। ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का ही सिद्धांत है। तो विजयवर्गीय अगर कोई नई जिम्मेदारी संभालते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपनी मौजूदा जिम्मेदारी को टाटा-टाटा, बाय-बाय



करना होगा। वो जिम्मेदारी क्या होगी वो हो सकती है टीम नितिन नबीन में जगह।

बीजेपी के नए अध्यक्ष की ताजपोशी होते ही ये अटकलें लगने लगी हैं कि अब उनकी टीम का कौन-कौन हिस्सा होंगे। नितिन नबीन के अनुभव को देखते हुए ये तय बात है कि उन्हें अपने साथ कुछ तजुबेकार चेहरों की जरूरत तो होगी ही। ये भी तय माना जा रहा है कि उनकी टीम में मध्यप्रदेश को अच्छा खासा वेटेज

विजयवर्गीय के अनुभव से बीजेपी को फायदा

सीनियर होने के नाते कैलाश विजयवर्गीय दूसरे प्रदेश के नेताओं को भी हैडल करना खुब जानते हैं। ऐसे में नितिन नबीन की टीम में उनके होने से बीजेपी को ही फायदा होगा। इससे बीजेपी को भी दो फायदे होंगे। एक तो केंद्रीय टीम में उनके जैसा एक्सपीरियंस नेता होगा। दूसरा प्रदेश कैबिनेट में चल रहा कोल्ड वॉर भी काफी हद तक कंट्रोल में आएगा।

मिलेगा। क्योंकि मप्र वह प्रदेश है जिसने बीजेपी को लंबे अरसे से निराश नहीं किया है।

बीजेपी का लॉयल स्टेट होने के साथ-साथ मप्र बीजेपी की ऐसी लैबोरेटरी भी रहा है। जहां किया गया हर प्रयोग बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है और इस बार तो प्रदेश ने अपनी सारी लोकसभा सीटें भी बीजेपी के ही खाते में डाल दी हैं। ऐसे में नितिन नबीन की टीम में भी मप्र का दबदबा दिख सकता है।

इस टीम के लिए सबसे आगे जो नाम बताए जा रहे हैं उन्होंने में से एक कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है।

यू देखा जाए तो कैलाशजी बीजेपी के तजुबेकार नेता तो हैं ही, संगठन को संभालने और मजबूत बनाए रखने की भी कला उनके पास है। मप्र की राजनीति का दमदार चेहरा होने के साथ-साथ वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपयोगिता बार-बार साबित करते रहे हैं। उन्हें पार्टी ने पश्चिम बंगाल का जिम्मा सौंपा था। जिसके बाद वो एक गैर हिंदीवादी प्रदेश में बीजेपी के नंबरस बढाने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा केंद्र में संगठन का जिम्मा संभालने का भी उनके पास अनुभव है। वो जेपी नड्डा की टीम में भी राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वो दोबारा इस या ऐसे किसी पद पर नजर आए तो हैरानी नहीं होगी। इसकी एक और वजह है विजयवर्गीय पार्टी के सीनियर नेताओं में से हैं। जिनकी धमक पूरे देश में बात चाहे उत्तरप्रदेश की हो, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ या किसी और हिंदीभाषी प्रदेश की हो। कैलाश विजयवर्गीय का नाम हर जगह जाना पहचाना है।

अग्रवाल महासंघ द्वारा देशी खेलों की रंगारंग स्पर्धाएं संपन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • विजय नगर अग्रवाल महासंघ ने मकर संक्रांति, पतंग उड़सव एवं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में समाजसेवी दीपचन्द्र अग्रवाल के आतिथ्य में रंगारंग स्पर्धाओं का आयोजन किया। अतिथि स्वागत महासंघ के संरक्षक किशोर गोयल, अध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं महामंत्री नीरज गोयल ने किया। इस मौके पर पतंगोत्सव, गिल्ली डंडा, सिताँलिया, दर्डीमार एवं अन्य देशी खेलों का आयोजन किया गया, जिनमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। महासभा के उपाध्यक्ष नितेश बंसल एवं संगठन मंत्री शैलेन्द्र अग्रवाल (महू) ने बताया कि कार्यक्रम में श्रीमती प्रीति-ऋषभ जैन, भवना-मनीष गर्ग, मेधा-विनय गुप्ता, आभा-नीरज गोयल के मार्गदर्शन में मनोरंजक खेलों का भी संचालन किया गया, जिनमें संध्या गर्ग, रुपाली सिंचल, शीतल अग्रवाल, स्वाति गुप्ता एवं सुश्री साक्षी गोयल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के समाज बन्धुओं ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। कार्यक्रम का संयोजन संदीप अग्रवाल, पवन अग्रवाल, पंकज अग्रवाल एवं मनीष गर्ग ने किया और अंत में आभार माना।



वेल्यूअर्स के अभा सेमीनार में जैन का सम्मान, स्मृति चिन्ह भेंट कर दी विदाई

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ वेल्यूअर्स द्वारा शहर में पहली बार होटल सयाजी में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार के दौरान शहर के वरिष्ठ वेल्यूअर्स डीके जैन का विशेष सम्मान किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप इन्साल्वेंसी प्रोफेशनल (आईपी) टीना सारस्वत पांडे एवं छाया गुप्ता भी उपस्थित रहीं। आयोजन समिति के समन्वयक अरविन्द अग्रवाल ने बताया कि पहली बार इंदौर में सम्पन्न हुए इस सेमीनार में देश के 12 राज्यों के 150 से अधिक वेल्यूअर्स शामिल हुए, जिन्होंने अपने-अपने व्यावसायिक अनुभवों एवं शोध कार्यों को एकट्ठे से साझा करते हुए वेल्यूअर्स के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव, गुणवत्ता एवं तकनीकी दृष्टिकोण पर विचार मंथन किया। समापन



प्रसंग पर आयोजन समिति की ओर से सुंदर पांडियन, जेम्स गोंजाल्विस, पराग कुलकर्णी, योगेन्द्र दुबे, संजय मित्तल, अभिभाषक रोहित दुबे, मनीष पाटक, पलक अग्रवाल एवं ललित काले ने देशभर से आए वेल्यूअर्स को देश की सबसे स्वच्छ नगरी इंदौर की ओर से स्मृति चिन्ह भेंटकर भावपूर्ण विदाई दी। अंत में समन्वयक अरविन्द अग्रवाल वेल्यूअर ने इस सफल एवं सार्थक आयोजन के लिए सबके प्रति आभार व्यक्त किया।

महंत हरिदास महाराज की चरण पादुका समाधि एवं भंडारा

दैनिक इंदौर संकेत

चंद्रावतीगंज • बुधवार को महंत हरिदास महाराज के निधन के बाद नगर में विधि-विधान से कार्यक्रम आयोजित किया गया। तेरहवें दिन चरण पादुका समाधि एवं विशाल भंडारा हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की भंडारे से पहले नगर में जुलूस के साथ अखाड़ा निकाला गया। यह वैष्णव हरि गार्डन से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस गार्डन में पहुँचा जुलूस का स्वागत नगरवासियों द्वारा जगह जगह मंच लगाकर पुष्प वर्षाकर स्वागत किया गया नगर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर कई साधु-संत और महंत उपस्थित रहे। महंत हरिदास जी महाराज की उपाधि अब महंत प्रेमदास जी महाराज को दी गई। उन्हें कंठी माला पहनाकर महंत का स्थान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में श्री श्री 1008 महंत रामचंद्र दास जी (दिगांबर अखाड़ा उज्जैन), श्री श्री 1008 महेंद्र



दिविजय दास जी (निर्बानी अखाड़ा उज्जैन), श्री श्री 1008 अर्जुन दास जी (खाकी अखाड़ा उज्जैन), श्री श्री 1008 महेंद्र चरण दास जी (निर्मोही अखाड़ा उज्जैन), पुजारी मोहनदास जी (दिगांबर अखाड़ा उज्जैन) और लाल दास जी पुजारी (दिगांबर अखाड़ा उज्जैन) सहित कई संत उपस्थित थे।

वरिष्ठ समाजसेवी प्रेमचंद गोयल को स्वागतार्थ्यक्ष, मोहनलाल बंसल एवं अनुप सिंचल को अर्थव्यवस्था, प्रमोद बिंदल को कन्यादान व्यवस्था, सतीश गुप्ता को चल समारोह, अखिलेश गोयल को नेकचार व्यवस्था, कैलाश चोमवाल को भोजन व्यवस्था समिति का संयोजक मनोनीत किया गया है।

हिंदू लड़की के शोषण का आरोप, बजरंग दल का हंगामा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • राऊ थाना क्षेत्र एक बार फिर लव जिहाद के गंभीर मामले को लेकर चर्चा में आ गया है। बजरंग दल ने खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि क्षेत्र स्थित होटल को लव जिहाद का अड्डा बनाया जा रहा है, जहां नाबालिग हिंदू युवतियों को बहला-फुसलाकर लाया जाता है। ताजा मामले एक युवक पर नाबालिग हिंदू युवती के साथ शोषण करने का गंभीर आरोप सामने आया है। विहिप के प्रचार प्रसार प्रमुख देवा शर्मा ने बताया कि आरोपी ने हिंदू नाबालिग लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर होटल में लाया। चोंकाने वाली बात यह रही कि होटल में कमरा लेने के लिए युवती का आधार कार्ड लगाया गया, जिसके आधार पर होटल प्रबंधन ने बिना किसी सत्यापन के कमरा उपलब्ध करा दिया।

'मोहन से महात्मा तक' दुआ सभागृह में सुश्री भारती दीक्षित की अनूठी प्रस्तुति

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • संस्था सेवा सुरभि द्वारा प्रवर्तित इंडा ऊँचा रहे हमारा अभियान का समापन शुक्रवार 30 जनवरी को रीगल चौराहा स्थित दुआ सभागृह में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के निर्वाण दिवस पर 'मोहन से महात्मा तक' शीर्षक भावपूर्ण आयोजन के साथ होगा।



संस्था के संयोजक ओमप्रकाश नरेड, अनिल त्रिवेदी एवं कुमार सिद्धार्थ ने बताया शहर कि प्रख्यात लेखक, चित्रकार और रंगकर्मी सुश्री भारती दीक्षित इस कार्यक्रम में बापू की दास्तानागोई प्रस्तुत करेंगी जिसमें 'मोहन से महात्मा तक' की संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायी जीवन यात्रा को बहुत दिलचस्प अंदाज में संयोजा गया है। बापू के जीवनवृत्त को सुश्री दीक्षित के माध्यम से नए अंदाज में सुनना सुधि श्रोताओं के लिए नया अनुभव होगा। कार्यक्रम के सूत्रधार होंगे प्रसिद्ध रंगकर्मी संजय पटेल। कार्यक्रम आम श्रोताओं के लिए खुला है, लेकिन प्रवेश 'पहले आए-पहले पाए' के आधार पर ही संभव होगा। इस आयोजन के साथ ही संस्था सेवा सुरभि द्वारा जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण की सहभागिता में गत 15 जनवरी से संचालित इंडा ऊँचा रहे हमारा अभियान का समापन हो जाएगा। भारती दीक्षित एक प्रतिष्ठित क्रिस्सागो और चित्रकार हैं, जिनका इतिहास, साहित्य, संस्कृति और प्रकृति से गहरा जुड़ाव है। वे कहानियों और अपनी कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति, परंपरा, वीरता को जीवंत करने और प्रकृति से जुड़ने का काम कर रही हैं। भारती के लिए क्रिस्सागोई और चित्रकला दोनों ही माध्यम उन्हें अपनी जुड़ों, प्रकृति और देश के इतिहास के करीब लाते हैं। भारती दीक्षित 'सुनें...कहानी भारत की' श्रृंखला के तहत भारत के वीरों, वीरांगनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, महत्वपूर्ण पलों और महान व्यक्तियों की कहानियां प्रस्तुत करती हैं।

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत

आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापटी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश निःशुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

डीन के भुगतान नहीं किए जाने के फरमान के बाद भी दौरी कपनी ने समाल लिया है काम

कार्यालय का पता

5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर, गुरुद्वारे के सामने, इंदौर

संपर्क: 94250-64357, 94245-83000

सम्पादकीय

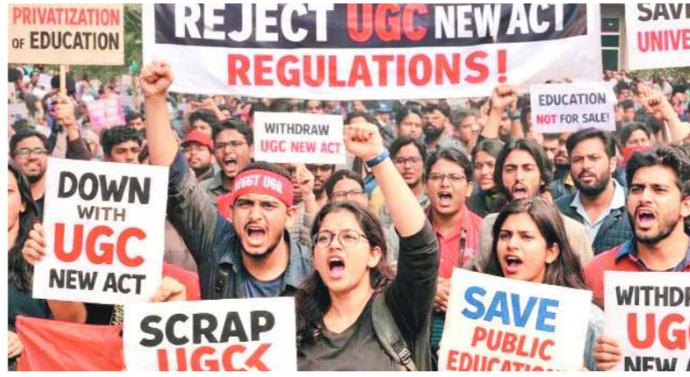
बारामती विमान हादसा -

अजित पवार की मौत ने फिर उठाए सवाल, क्या सबक अब भी नहीं?

कहा जा रहा है कि अजित पवार के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हवाई यातायात नियंत्रण ने पायलट से पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, तो जवाब 'नहीं' था। इसके बाद विमान ने आसमान में ही एक चक्कर लगाया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित पांच लोगों को एक विमान हादसे में मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना है। इस त्रासदी ने न केवल देश के एक कुशल नेता को छीन लिया, बल्कि उन दर्दनाक हादसों की कड़वी यादें भी ताजा कर दीं, जिनमें पहले भी देश ने कई राजनीतिक दिग्गजों और प्रमुख हस्तियों को असमय खोया है। पुणे जिले के बारामती में हुए इस हादसे की अब कई कोणों से जांच की जा रही है, मगर सवाल है कि इससे पहले हुई ऐसी दुर्घटनाओं से क्या सरकारी तंत्र ने कोई सबक नहीं लिया? आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ, उस वक्त हवाई अड्डे पर दृश्यता कम थी। अगर स्थिति वास्तव में जोखिमपूर्ण थी, तो विमान को उतरने की अनुमति क्यों दी गई? दूसरा, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में क्या ऐसी आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए हवाई अड्डों पर विशेष व्यवस्था नहीं की जा सकती है? उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान बुधवार सुबह पुणे जिला के बारामती में हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नीचे आने के बाद उसमें धमाके के साथ आग लग गई। इस हादसे में अजित पवार सहित विमान में सवार सभी पांच लोगों की जान चली गई। इससे पहले वर्ष 1980 में कांग्रेस नेता संजय गांधी, वर्ष 2001 में माधवराव सिंधिया, वर्ष 2011 अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू, वर्ष 2021 में तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वर्ष 2025 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जैसे दिग्गजों को भी देश ने विमान दुर्घटनाओं में खोया है। कहा जा रहा है कि अजित पवार के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले हवाई यातायात नियंत्रण ने पायलट से पूछा कि क्या रनवे दिखाई दे रहा है, तो जवाब 'नहीं' था। इसके बाद विमान ने आसमान में ही एक चक्कर लगाया। इससे स्पष्ट है कि हवाई अड्डे पर परिस्थितियां विमान को उतरने के अनुकूल नहीं थीं। यह दावा भी किया जा रहा है कि दूसरी बार पूछे जाने पर पायलट ने सकारात्मक जवाब दिया। मगर सवाल है कि क्या किसी तरह के जोखिम को आशंका के बीच विमान को उतारने की अनुमति दी जा सकती है? अजित पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और भाजपा के नेतृत्व वाली कई सरकारों में उपमुख्यमंत्री रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार की छत्रछाया से बाहर निकल कर उन्होंने जुलाई 2023 में पार्टी के नाम और विचारों के साथ-साथ दल के ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में कर लिया था।

यूजीसी : यूनिवर्सिटी-कॉलेज में जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर राय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 13 जनवरी 2026 को नए नियमों को लागू किया है, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया में RollbackUGC ट्रेड कर रहा है। इसे यूजीसी का काला कानून बताकर विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि इस नए नियम के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को संभावित अपराधी करार दे दिया गया है। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए शुरू हुई ये कवायद सियासी विवाद की शकल ले रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गौरतलब है कि जीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 17 दिसंबर 2012 से ही जातीय भेदभाव रोकने के खिलाफ कुछ सलाहकारी नियम लागू हैं। इसे उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से जुड़े नियम बताया गया है। इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं था। परन्तु यह जानना जरूरी है कि इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बारे में बताया जाता है कि जनवरी 2016 में तेलंगाना में रोहित वेमुला और मई 2019 को पायल टाडवी के आत्महत्या के मामलों के बाद पीड़ित परिजनों ने 29 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और जातीय भेदभाव की शिकायतों पर कठोर नियमों की मांग की। जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तब को जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर डेटा जुटाने और नए नियम बनाने का निर्देश जनवरी 2025 में दिया था। फरवरी 2025 में एक ड्राफ्ट जारी किया गया। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग छात्र संघ का कहना है कि कि ओबीसी को जातिगत भेदभाव की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है। उन्हें समानता समिति में शामिल नहीं किया जाता है। ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों के लिए सजा का भी प्रावधान था। उनका तर्क था कि इससे शिकायतों करने वालों में ऐसे मामलों की जानकारी न देने का डर बैठ सकता है। ओबीसी छात्र संघ के मुताबिक, इसमें जातिगत भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा नहीं बताई गई है, लिहाजा नए नियमों की जरूरत है। सरकार की ओर से जो पहला बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि यह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान के इस बयान में प्रदर्शनकारियों को कोई बड़ी राहत वाली नजर नहीं आई और उनकी चिंताएं जस की तस हैं। ऐसे में इस बात पर गहराई से नजर डालते हैं कि यूजीसी के नियम के मायने क्या हैं और इन नियमों



में आखिर ऐसी क्या चिंताएं हैं कि स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स-प्रोफेसर्स तक प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। यूजीसी की ओर से कहा गया है कि इस नियम का उद्देश्य है कि वह उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और असमानता पर रोक लगा सके। नए नियम के अनुसार, सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज Equity Center, Equity Squad और Equity Committee बनाएंगे। साथ ही 24x7 हेल्पलाइन भी रहेगी। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता, तो तब उनकी मान्यता रद्द कर सकता है या फंड रोक सकता है। यूजीसी का कहना है कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ शिकायतों में 2020 से 2025 के बीच 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके अलावा रोहित वेमुला और पायल टाडवी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह नियम बनाया जा रहा है। नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह आएंगे हैं, जो सिर्फ सलाह की तरह थे, जबकि नए नियमों का पालन करना अब सभी संस्थानों के लिए जरूरी होगा। पांच पॉइंट्स में पूरी कहानी समझिए इन नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक 'इक्विटी कमेटी' बनाना जरूरी होगा। यह कमेटी भेदभाव से जुड़ी शिकायतें देखेगी और यह तय करेगी कि किसी के साथ गलत व्यवहार न हो। इस कमेटी में 'SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं' का प्रतिनिधित्व रहना सबसे जरूरी होगा। इन नियमों का ड्राफ्ट पिछले साल फरवरी में सार्वजनिक किया गया था और उस पर सुझाव मांगे गए थे। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के उस

निर्देश के बाद आएंगे, जिसमें अदालत ने रोहित वेमुला और पायल टाडवी की माताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान तब से नए नियम पेश करने को कहा था। यह याचिका 2012 के नियमों को लेकर बहुत कमजोर और उदासीन रुख से जुड़ी थी। यानी ये नियम बस मौजूद था, लेकिन इसके प्रति सक्रियता नहीं थी। इसके साथ ही हर संस्थान में एक 'इक्विटी ऑफिसियल सेंटर' भी बनाया जाएगा, जो कमजोर और वंचित वर्गों के छात्रों को बढ़ावा देगा। सामाजिक और मानसिक सहयोग देगा। खासतौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकना और उच्च शिक्षण संस्थानों में पूरी तरह समानता मिले। 2012 के नियम सिर्फ सलाह की तरह थे, लेकिन 2026 के नए नियम जरूरी और अनिवार्य बन जाते हैं और संस्थानों को इन नियमों के तहत काम करना ही होगा। यानी इक्विटी ऑफिसियल सेंटर, इक्विटी कमेटी, हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र बनाने ही होंगे। इन नियमों को लेकर कई जगह विरोध हो रहा है, खासकर जनरल कैटेगरी के कुछ लोग कह रहे हैं कि नए नियम उनके लिए ठीक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि नियमों में 'जाति-आधारित भेदभाव' को सिर्फ SC, ST और OBC तक सीमित कर दिया गया है। इससे जनरल कैटेगरी के लोगों को संस्थागत सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इस तरह ये नियम उनके लिए भेदभाव से भरे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि रेगुलेशन 3(C) जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा को केवल SC, ST और OBC तक सीमित कर देता है। इसमें कहा गया है कि जाति-आधारित भेदभाव वही माना जाएगा, जो केवल इन वर्गों के खिलाफ हो। वहीं रेगुलेशन 3(e) में 'भेदभाव' को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी तरह के अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस तरह की परिभाषा से जनरल या गैर-आरक्षित वर्ग के छात्र और शिक्षक, जो जाति के आधार पर उन्नीसवां पक्षपात का सामना कर सकते हैं, उन्हें संस्थागत संरक्षण और शिकायत निवारण से वंचित कर दिया गया है। नियमों के मुताबिक, किसी के साथ 'धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता' के आधार पर गलत या पक्षपातपूर्ण व्यवहार भेदभाव माना जाएगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि परिभाषा साफ नहीं है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अब संस्थान के प्रमुख को यह देखना होगा कि कैम्पस में कोई भेदभाव न हो। शिकायत के लिए 'ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन' होगी। अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है और उसे तब की योजनाओं से बाहर भी किया जा सकता है। हर शब्द को एक इक्विटी ऑफिसियल सेंटर बनाना है। एकेडमिक और सामाजिक काउंसिलिंग और कैम्पस में विविधता को बढ़ावा देना इस सेंटर के तहत बनने वाली इक्विटी कमेटी में हस्त, स्त्र, स्त्र और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। यह कमेटी भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। जिस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, उसमें एक बड़ी चिंता शामिल है। विरोधियों और आलोचकों का कहना है कि इन नियमों में 'झूठी शिकायतों' से निपटने का कोई साफ नियम नहीं है और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व की बात भी नहीं की गई है। यानी चिंता ये भी है कि अगर विवाद की स्थिति बनती है तो कमेटी के सदस्य अपने पूर्वाग्रहों के कारण एकतरफा हो सकते हैं। इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसी वजह से इन नियमों पर बहस जारी है। कुल मिलाकर, नियमों का मकसद समानता लाना है, लेकिन नियम जिस भाषा और शैली में लाए गए हैं, और इसके दायरों को जिस तरह से सीमित कर दिया गया उसे लेकर की सवाल खड़े हो रहे हैं।

अशोक भाटिया,
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक
समीक्षक एवं टिप्पणीकार

आंचलिक



ट्रांसफर रोकने छात्रों का मार्च, 'सर को वापस लाओ' के नारे लगाए

दैनिक इंदौर संकेत
खरगोन • सेगांव में बुधवार को एक शिक्षक के ट्रांसफर के विरोध में 200 से अधिक छात्र और अभिभावक सड़क पर उबर आए। साहिबपनी स्कूल के शिक्षक नटवर पाटीदार का अटैचमेंट रद्द कराने की मांग को लेकर वे सर को वापस लाओ के नारे लगाते हुए खरगोन कलेक्ट्रेट के लिए पैदल निकल पड़े। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद डिप्टी कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक की वापसी का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शन खत्म हुआ। विद्यार्थी और अभिभावक स्कूल से रवाना हुए। सेगांव से गुजरते समय तहसीलदार अंतर सिंह कनेश, पुलिस चौकी प्रभारी गजेन्द्र चौहान और बीआरसी संदीप कापरनीस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। छात्र और अभिभावक अपनी मांग पर अड़े रहे और नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च जारी रखा।

सड़कों पर उतरा सर्व समाज ने यूजीसी कानून के खिलाफ रैली निकाली



दैनिक इंदौर संकेत
खरगोन • सर्व समाज के लोगों ने यूजीसी के नए कानून के विरोध में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने इसे 'काला कानून' बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी है कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया, तो वे भाजपा के बजाय नोटो दा देंगे। रैली के बाद तहसीलदार दिनेश सोनरतिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राधा वल्लभ मार्केट स्थित परशुराम चौक से रैली शुरू हुई। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुराने कलेक्टर ऑफिस परिसर पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष नारेबाजी करते हुए शामिल हुए। यहां सभी ने एक सुर में कानून का विरोध किया। सर्व समाज के प्रतिनिधि राजू शर्मा ने कहा कि 'एक ओर देश में जात-पात खत्म करने के लिए हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ऐसे 'काले कानून' लाकर समाज में भेदभाव पैदा कर रही है।' उन्होंने कहा कि 'सरकार को गौ हत्या, धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने चाहिए थे, न कि ऐसा कानून जो समाज को तोड़ने वाला हो।'
'सर्वर्णों का जीवन मुश्किल हो रहा'
प्रदर्शन में शामिल ममता जितेंद्रसिंह सोलंकी ने कहा कि 'एससी-एसटी और यूजीसी जैसे कानून देश में सर्वर्णों के लिए जीवन मुश्किल बना रहे हैं।' उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि 'कहीं देश में सर्वर्णों की स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं जैसी न हो जाए।'

पकड़ी गई पटाखा फैक्ट्री, आरोपी फरार, 2 हजार किग्रा बारूद मिला



दैनिक इंदौर संकेत
खंडवा • जिले में पहली बार सोमवार देर रात पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई। यह फैक्ट्री पड़ेला हनुमान मंदिर रोड पर सुनसान कॉलोनी सम्यक गोल्ड के क्लब हाउस में संचालित हो रही थी। पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी फरार हो गए। मौके से एक पिकअप वाहन, स्कूटर और 2,000 किलो बारूद जब्त किया गया। पिकअप वाहन के संचालक से पूछताछ की गई। पुलिस ने बताया कि यदि यहां विस्फोट होता तो तीन किलोमीटर तक इसका असर पड़ सकता था। एसपी मनोज कुमार राय ने कहा कि मुख्य संदेही कांग्रेस नेता हैं। क्लब हाउस पर कब्जा कांग्रेस नेता यशवंत सिलावत का था, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया है। सीएसपी अभिनव बारगे ने बताया कि फैक्ट्री में 70 बोरे सुतली बम और 50-50 किलो सल्फर व एल्यूमीनियम पाउडर पाए गए। सुरक्षा व्यवस्था न होने की वजह से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के सरकारी बंगले, कॉलोनी और सिहाड़ा ग्राम तक इसका असर पड़ सकता था। सीएसपी अभिनव बारगे ने बताया कि फैक्ट्री में 70 बोरे सुतली बम और 50-50 किलो सल्फर व एल्यूमीनियम पाउडर पाए गए। सुरक्षा व्यवस्था न होने की वजह से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के सरकारी बंगले, कॉलोनी और सिहाड़ा ग्राम तक इसका असर पड़ सकता था।

तेज हवा-बारिश से गेहूं, चना, मक्का की फसलें प्रभावित



दैनिक इंदौर संकेत
बुरहानपुर • जिले में मंगलवार रात तेज हवाओं और बारिश के कारण गेहूं, चना और मक्का की फसलों को नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सबसे अधिक क्षति बुरहानपुर क्षेत्र में हुई है, जबकि शाहपुर, खकनार और नेपानगर के कुछ गांवों में भी फसलों के प्रभावित होने की सूचना है। राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन करने में जुटी है, जिसके बाद विस्तृत सर्वे शुरू किया जाएगा। खंडवा संसदीय सीट से सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने केंद्रीय कृषि मंत्री

शिवाजी सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से फोन पर चर्चा कर स्थिति से अवगत कराया। जिले के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। किसानों को सुबह खेतों में पहुंचने पर वास्तविक स्थिति का पता चला। निंबोला क्षेत्र में लगभग 50 से 60 किसानों की गेहूं, चना और मक्का की फसलें प्रभावित हुई हैं, जिनमें निंबोला चुलखान और मगरूल गांव शामिल हैं। अक्टूबर-नवंबर में बोई गई गेहूं की फसल को विशेष रूप से नुकसान पहुंचा है, जिसमें बालियां निकल चुकी थीं। गेहूं और चने के फूल झड़ने से उत्पादन में कमी आने की आशंका है। तेज हवा से गेहूं की फसल आड़ी हो गई है, जिससे दाने बारीक रह सकते हैं। किसान बाढ़ लक्ष्मण भावसे ने बताया कि उनकी दो एकड़ गेहूं और दो एकड़ चने की फसल को तेज हवा के कारण नुकसान हुआ है। अन्य किसानों को भी इसी तरह की क्षति हुई है।

केंद्रीय बजट का प्रचार-प्रसार करेगी भाजपा, जिला उपाध्यक्ष को दी कमान



दैनिक इंदौर संकेत
खंडवा • केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए आम बजट को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रदेशभर के सभी जिलों में विशेष कमेटियों का गठन किया गया है, जो बजट में शामिल जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएंगी। भाजपा संगठन की ओर से नियुक्त की गई इन कमेटियों में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल किए गए हैं। ये कमेटियां गांव-गांव, वार्ड स्तर पर बैठकें, संवाद कार्यक्रम एवं जनसंपर्क के माध्यम से केंद्र सरकार के बजट की प्रमुख विशेषताओं को जनता के सामने रखेंगी। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि बजट में किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बजट से जुड़ी योजनाओं, टैक्स राहत और विकास से संबंधित प्रावधानों की सरल भाषा में जानकारी दें, ताकि आम नागरिक बजट के लाभों को समझ सकें। खंडवा में केंद्रीय बजट के प्रचार-प्रसार के लिए 7 लोगों की कमेटी बनाई गई है, इस टोली का संयोजक जिला उपाध्यक्ष सुधांशु जैन को बनाया गया है। वहीं बाकी सदस्यों में जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष राजपालसिंह तोमर ने बताया कि यह अभियान तय कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और इसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

फाइनल में एंट्री के लिए उतरेगी मंधाना की टीम, यूपी वॉरियर्स से मुकाबला आज

नई दिल्ली (एजेंसी) • अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (आरसीबी) लगातार दो मैच में हार को पीछे छोड़कर यूपी वॉरियर्स के खिलाफ गुरुवार को वडोदरा में होने वाले महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के मैच में जीत दर्ज करके फाइनल में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेगा। आरसीबी (10 अंक) डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने वाली एकमात्र टीम है, लेकिन वॉरियर्स के खिलाफ जीत से उसकी फाइनल में



जगह भी पक्की हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए कड़ी चुनौती का सामना कर रही वॉरियर्स की टीम को अपनी शीर्ष स्कोरर फोबे लिचफील्ड (243 रन)

की चोट से बड़ा झटका लगा है। लिचफील्ड टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और एमी जोन्स को उनके स्थान पर टीम में शामिल किया गया है। स्मृति मंधाना की अगवाई वाली आरसीबी की टीम पहले पांच मैच जीत कर सभी टीमों से काफी आगे निकल गई थी, लेकिन उसके बाद मिली दो हार ने निश्चित रूप से उसके अभियान को झटका लगा है। वहीं वॉरियर्स की टीम अभी सबसे निचले पायदान पर है और उसके लिए अब करो या मरो जैसी स्थिति बन गई है क्योंकि शीर्ष तीन टीम में जगह बनाने के लिए उसे न सिर्फ अपने बाकी बचे मैच जीतने होंगे, बल्कि अगर मगर की कटिन डार से भी गुजरना पड़ेगा।

नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मुसेटी के टूर्नामेंट से हटने पर मिला वॉकआउट



मेलबर्न (एजेंसी) • रिकॉर्ड 10 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच का भाग्य ने साथ दिया और वह बुधवार को मेलबर्न में लॉरेन्सो मुसेटी से पहले दो सेट हारने के बाद भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। वजह यह रही कि क्वार्टर फाइनल में जोकोविच के खिलाफ पहले दो सेट जीतने के बाद पांचवीं वरीयता प्राप्त मुसेटी चोट के कारण टूर्नामेंट से हट गए, जिससे जोकोविच को वॉकआउट मिल गया। इस तरह से 38 वर्षीय जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपना 11वां खिताब और कुल 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की कवायद जारी रखी, लेकिन उनका कहना है कि इस बार वह भाग्यशाली रहे। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला दो बार के मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन यानिक सिनर और आठवें नंबर के खिलाड़ी बेन शेल्टन के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। महिला वर्ग में पांचवीं वरीयता प्राप्त एलिना रयबाकिना और छठी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका आमना-सामना होगा। रयबाकिना ने विश्व में दूसरे नंबर की खिलाड़ी इगा स्विजातेक को 7-5, 6-1 से, जबकि छठी वरीय पेगुला ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी और यहां चौथी वरीयता प्राप्त अमांडा अर्निंसिमोवा को 6-1, 7-6 (6-1) से हराया।

पामेला के मार्गदर्शन में उतरेगी भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम

नई दिल्ली (एजेंसी) • भारतीय महिला अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम मुख्य कोच पामेला कौंटी के मार्गदर्शन में 1 से 12 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एएफसी एशियाई कप में उतरेगी। इसके बाद एएफसी महिला अंडर-17 एशियाई कप 30 अप्रैल से 17 मई तक चीन में खेला जाएगा। पामेला इटली की पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं और कोच के तौर पर उनकी पहली परीक्षा टूर्नामेंट सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2026 होगा जो 31 जनवरी से सात फरवरी तक नेपाल के पोखरा में आयोजित होगा।



फुटबॉल महासंघ ने कहा है कि पामेला अंडर-17 महिला टीम के महाद्वितीय टूर्नामेंट की तैयारी के ट्रेनिंग शिविर में शामिल हो गई हैं। ये टूर्नामेंट आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में खेला जा रहा है। कौंटी के सहायक स्टाफ के रूप में उनके भाई विसेजो कौंटी सहायक कोच के तौर पर रहेंगे। वहीं निवेशा रामदोस सहायक कोच के तौर पर होंगी इटली की पूर्व अंतरराष्ट्रीय मिडफील्डर पामेला के को खेल और कोचिंग का अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव का है। अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने इटली महिला राष्ट्रीय टीम के लिए 90 मैच खेले और 30 गोल किए हैं।

सेहत को लेकर मजेदार किस्सा सुनाया ऋतिक रोशन ने



मुंबई (एजेंसी) • फिल्म निर्माता गोल्डी बहल की बर्थडे पार्टी में अभिनेता ऋतिक रोशन को बेसाखी के सहारे चलते देखा गया था, जिसके बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए थे। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी वजह साफ कर दी है। ऋतिक ने बताया कि उनके बाएं घुटने में अचानक दर्द उभर आया, जिससे चलने-फिरने में दिक्कत होने लगी। उन्होंने लिखा कि उनके शरीर के हर हिस्से में जैसे कोई 'ऑन/ऑफ' बटन लगा हो। कभी बायां पैर जवाब दे देता है, तो कभी कंधा या दायां टखना अचानक काम करने से मना कर देता है। ऋतिक ने इसे सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि एक तरह की मनोदशा भी बताया। अपने खास अंदाज में उन्होंने लिखा, 'कभी मेरे बाएं पैर को बेसाखी की जरूरत पड़ती है, तो कभी बायां कंधा और दायां टखना एक्टिव हो जाते हैं या अचानक बंद हो जाते हैं। लगता है मेरे शरीर के हर हिस्से की अपनी अलग ही मर्जी है।' ऋतिक ने अपनी हालिया शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक गंभीर सीन के दौरान उनका डायलॉग था 'क्या आप डिनर के लिए घर आना चाहेंगे?' लेकिन उनकी जुबान 'डिनर' शब्द बोलने से मना कर रही थी। ऐसे में उन्होंने हर टेक में चतुराई से 'डिनर' की जगह 'लंच' कहना शुरू कर दिया, क्योंकि शुक था कि 'लंच' शब्द अभी भी बोला जा सकता था।

फिटनेस को लेकर गंभीर हैं अक्षरा सिंह

मुंबई (एजेंसी) • फिटनेस और मेहनत का अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने फिर शानदार नमूना पेश किया है। अभिनेत्री अपनी फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर हैं और नियमित रूप से जिम में एक्सरसाइज करती हैं। उन्होंने अपनी कुछ नई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जिनमें वे अपनी टोंड और फिट बॉडी फ्लॉन्ट करती नजर आईं। उनकी यह फिटनेस मोटिवेशन का स्रोत बनी हुई है। इस बार भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे लटकते हुए पुल-अप और हेंगिंग लेग रेज करती दिख रही हैं। कुछ तस्वीरों में वे ओपन जिम में एक्सरसाइज करती दिख रही हैं, तो कुछ में उनके मजबूत आर्मस, टाइट एक्स और संपूर्ण फिट बॉडी साफ नजर आ रही है। स्पॉट्सविवर में उनका लुक एनर्जेटिक और आकर्षक लग रहा है। तस्वीरों को देखकर फैंस अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्षरा फिटनेस को कितनी गंभीरता से लेती हैं। पोस्ट में उन्होंने सिर्फ एक इमोजी का इस्तेमाल किया है, लेकिन फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।



उज्जैन संभाग

भू-अधिग्रहण विवाद, प्रभावित किसानों की मीटिंग, बड़े आंदोलन की तैयारी

दैनिक इंदौर संकेत
उज्जैन • उज्जैन को इंदौर और जावरा से जोड़ने के लिए बनाए गए करीब 7 हजार करोड़ की दो ग्रीन फील्ड सड़कों का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों सड़कों से प्रभावित उज्जैन, इंदौर और रतलाम जिले के 90 गांव के किसानों ने अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली। सभी 25 फरवरी से उज्जैन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की योजना बना ली है। आंदोलन को लेकर सोमवार शाम को उज्जैन-इंदौर ग्रीन फील्ड प्रभावित 28 गांवों के किसानों की इंदौर जिले के ग्राम चित्तौड़ा में बैठक हुई। इसमें किसानों ने आरपार की लड़ाई की योजना बना ली। उज्जैन और इंदौर जिले की किसानों की इस संयुक्त मीटिंग में आगामी 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का

निर्णय लिया है। प्रदर्शन उज्जैन कलेक्टोरेट परिसर में होगा। बैठक में निर्णय लिया कि आरपार की इस लड़ाई में उज्जैन-इंदौर ग्रीन फील्ड रोड के 28 गांवों के साथ ही उज्जैन-जावरा रोड प्रभावित 62 गांव के किसानों ने भी शामिल होने की सहमति दे दी है। यानी उज्जैन जिले के किसानों के साथ इस आंदोलन में उक्त दोनों ग्रीन फील्ड सड़कों से प्रभावित इंदौर व रतलाम जिले के गांव के किसान भी शामिल होंगे। इंदौर और जावरा से जोड़ने के लिए दो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल रोड बनाए जाना है। जिले को इंदौर से जोड़ने वाले ग्रीन फील्ड से उज्जैन के 7 और इंदौर जिले के 21 गांव प्रभावित होंगे। वहीं उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड से उज्जैन के 49 और रतलाम जिले के 13 गांव प्रभावित हो रहे हैं। दोनों हाई-वे में कुल 56 गांव प्रभावित होंगे।

16 लाख की चोरी, मंदिर में भगवा धोती, जूते पहने खिड़की से गर्भगृह में घुसा था बदमाश

दैनिक इंदौर संकेत
उज्जैन • प्राचीन आशापुरी मां भवानी मंदिर में चोरी हो गई। बदमाश यहां से 4 किलो से अधिक चांदी के जेवर ले गए। इनकी कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि एक चोर खिड़की के अंदर से अंदर आता है, जबकि दूसरा खिड़की के बाहर खड़ा रहता है। मंदिर में घुसा चोर माताजी को प्रणाम करता है। फिर एक बाल्टी के सहारे चांदी के छत्र उतारता है। इसके बाद अन्य रजत आभूषण लेकर चला जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदमाश दो नहीं, बल्कि तीन थे। चोरों ने माता जी का चांदी का छत्र, नथनी, हार सहित लगभग 4 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। चोर जूते पहने हुए माता जी के ओटले पर चढ़कर चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि दो अन्य चोर खिड़की के पास खड़े नजर आते हैं।

कोर्ट परिसर में दो पक्षों में विवाद, पेशी में पहुंचे थे

दैनिक इंदौर संकेत
आगर - मालवा • जिला न्यायालय परिसर में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दरअसल, दोनों पक्ष पेशी पर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों गुटों में कहासुनी हो गई, दो बाद में हाथापाई में बदल गई। घटना बुधवार दोपहर की है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और उनके बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। घटना के बाद न्यायालय परिसर में कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया था। ग्राम भादवा निवासी बहादुर (32) और गोविंदसिंह (35), दोनों पिता बनेसिंह राजपूत, का राजेंद्र सिंह (35) और ईश्वर सिंह (55), दोनों पिता ईश्वरसिंह, के साथ जमीन विवाद है। दोनों पक्ष पेशी के लिए न्यायालय पहुंचे थे, जहां किसी बात पर विवाद शुरू हुआ और गाली-गलौज के बाद हाथापाई में बदल गया। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के बीच लात-धुंसे चले। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया। कुछ अधिकतारों ने भी स्थिति को शांत करने में सहयोग



किया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। अतिरिक्त बल की सहायता से दोनों पक्षों को नियंत्रित किया गया और मारपीट में शामिल लोगों को कोतवाली थाने ले जाया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है।

कुश्ती से राज्य स्तरीय खेलों की शुरुआत अनुष्का और गौरव ने जीता स्वर्ण

दैनिक इंदौर संकेत
उज्जैन • राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के तहत चार खेलों का आयोजन किया जा रहा है। राजमाता सिंधिया खेलो स्टेडियम परिसर में कुश्ती प्रतियोगिता से इसकी शुरुआत हुई है। लोटी मैदान में मलखंब प्रतियोगिता चल रही है, जबकि आगामी दिनों में योगासन और रस्साकशी का आयोजन किया जाएगा। दरअसल, भोपाल के ताल्या टोपे स्टेडियम में मंगलवार को खेली एमपी यूथ गेम्स 2025-26 का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर खिलाड़ियों को शपथ दिलाई और विभिन्न संभागों से आए खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। मध्यप्रदेश शासन के खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर से चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। आयोजन में 1300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के आवास, भोजन और परिवहन की समस्त व्यवस्थाएं शासन द्वारा की गई हैं।
अनुष्का बौरासी और गौरव ने जीता स्वर्ण - उज्जैन में हुई कुश्ती प्रतियोगिता के प्रारंभिक परिणाम भी सामने आए हैं। अनुष्का बौरासी और गौरव यादव (जबलपुर) ने स्वर्ण पदक जीता। कात्यायनी देवी (रीवा) और गौतम पटौना (उज्जैन) ने रजत पदक हासिल किया। भूमिका (उज्जैन), फरहान खान (छिंदवाड़ा) और पृथ्वी जोशी (इंदौर) को कांस्य



पदक मिला। जिला खेल अधिकारी ओपी हरोड़ ने बताया कि खेलो एमपी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण, शहरी और आदिवासी अंचलों से खिलाड़ियों को जोड़ना है। इस संस्करण में एक लाख से अधिक खिलाड़ियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। चयनित खिलाड़ी 28 खेलों में राज्य स्तरीय मुकाबलों में भाग ले रहे हैं। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया पहल से प्रेरणा लेकर प्रदेश स्तर पर खेलो एमपी की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य कुश्ती सहित अन्य पारंपरिक और आधुनिक खेलों को बढ़ावा देना है। इससे पहले वर्ष 2023 में खेलो इंडिया का आयोजन हुआ था, जिसमें देश के 27 राज्यों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। उसी तर्ज पर खेलो एमपी को भी प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा मंच बनाया जा रहा है।

100 एकड़ में बनेगा फूलों का मेगा वलस्टर सिंहस्थ को लेकर उद्यानिकी विभाग की तैयारी

दैनिक इंदौर संकेत
उज्जैन • सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 100 एकड़ जमीन पर फूलों का विशेष उत्पादन वलस्टर विकसित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर यह वलस्टर धार्मिक नगरी उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में फूलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ किसानों को स्थायी आय का साधन देगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया कि उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर साल भर फूलों की बड़ी मांग रहती है। इसी को देखते हुए सरकार ने उज्जैन के आसपास व्यावसायिक पुष्प उत्पादन वलस्टर विकसित करने की कार्य योजना बनाई है। मंत्री कुशवाहा ने कहा कि सिंहस्थ मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं और पूजा-अर्चना के लिए फूलों की मांग कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में बाहर से फूल मंगाने की बजाय स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित फूलों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे परिवहन लागत घटेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। वलस्टर के माध्यम से उज्जैन और आसपास के किसानों को गुलाब, गेंदा, जरबेरा, रजनीगंधा, सेवंती, ग्लोडियोस जैसे अधिक मांग वाले फूलों की वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पुष्प उत्पादन को केवल पारंपरिक खेती से मानते हुए कृषि-उद्यम के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मंत्री कुशवाहा ने कहा कि मध्यप्रदेश पहले से ही पुष्प उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

उज्जैन बना देश में आईएसओ प्रमाण पत्र वाला दूसरा जिला

दैनिक इंदौर संकेत
उज्जैन • जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उज्जैन ने प्रशासनिक उत्कृष्टता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। यह सम्मान पूरे देश में अहमदाबाद के बाद उज्जैन जिला शिक्षा कार्यालय को प्राप्त हुआ है। यह सम्मान प्राप्त करने वाला उज्जैन देश का दूसरा जिला है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यालयीन व्यवस्था को पूर्णतः सुव्यवस्थित, आधुनिक एवं नागरिक हितैषी बनाए जाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार किए गए। कार्यालय के प्रत्येक कक्ष को सुसज्जित कर नामकरण किया गया। अभिलेखों का वैज्ञानिक पद्धति से संधारण किया और पुराने रिकॉर्ड को भंडार कक्ष में व्यवस्थित रूप से संरक्षित किया गया। इसके साथ ही कार्यालय में सभाकक्ष, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) कक्ष और आईटी सेल का निर्माण किया गया। कार्यालय



तक आने वाले पहुंच मार्ग पर पौधारोपण कर परिसर को हरित एवं सुंदर बनाया है। स्वच्छता के विशेष मानकों के अंतर्गत शौचालयों को स्वच्छ एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया है। पानी की व्यवस्था, सफाई एवं पेयजल के लिए आरओ प्रणाली की स्थापना की गई सुधारात्मक व नवाचारात्मक कार्यों के परिणामस्वरूप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को आईएसओ प्रमाण पत्र दिया। यह प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सांदिपनि वीडियो, महाराजवाड़ा क्रमांक-3 में भ्रमण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी को प्रदान किया गया। प्रमाण पत्र देते हुए मुख्यमंत्री।

न्यूज ब्रीफ

जिले में बिजली कनेक्शन की संख्या बढ़कर 11 लाख हुई

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • मध्य प्रदेश में बिजली कनेक्शन कंपनी द्वारा कैलेंडर वर्ष 2025 में 1.77 लाख नए बिजली कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह पिछले वर्ष से करीब सात हजार ज्यादा है। इंदौर राजस्व संभाग में करीब 1.10 लाख कनेक्शन जारी हुए हैं। पिछले बारह माह के दौरान इंदौर जिले में 53 हजार से अधिक कनेक्शन जारी हुए हैं। इन्हें मिलाकर इंदौर जिले में अब 11 लाख से ज्यादा बिजली कनेक्शन हो चुके हैं। इसमें से इंदौर शहर में करीब आठ लाख एवं देहात में तीन लाख से ज्यादा कनेक्शन विद्यमान हैं। इंदौर जिले में कृषि श्रेणी के ही 70 हजार से ज्यादा कनेक्शन हैं। कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने बताया कि इंदौर के बाद सबसे ज्यादा कनेक्शन उज्जैन जिले में 17300 कनेक्शन जारी हुए हैं। 11000 कनेक्शनों के साथ रतलाम जिले में भी तीव्र वृद्धि दर्ज हुई है। श्री सिंह ने बताया कि धार जिले में 10950 देवास जिले में 9586 नए कनेक्शन वर्ष 2025 में जारी किए गए हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री परमार आज इंदौर आएंगे

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग मंत्री इन्दर सिंह परमार गुरुवार, 29 जनवरी को इंदौर आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंत्री परमार आज दोपहर 3 बजे इंदौर पहुंचेंगे। वे यहां श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री श्री परमार शाम 6 बजे इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होंगे।

भारत और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील से राज्यों को भी मिलेगा लाभ-यादव

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भारत में आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ यह ट्रेड डील अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इस डील से देशभर में वस्तुएं सस्ती होंगी और राज्यों को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ट्रेड डील हमारी अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी।

चुनावी राज्यों में दिखेगा मप्र के नेताओं का दम

भाजपा चुनावी रणनीति में माहिर नेताओं को भेजेगी मोर्चे पर

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
भोपाल • जब भी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होता है, वहीं मप्र के भाजपा नेता रणनीति बनाते से लेकर चुनाव प्रचार तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी का परिणाम है कि चुनावी राज्यों में मप्र भाजपा के नेताओं की तैनाती हर मोर्चे पर की जाती है। इस वर्ष देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जहां चुनावी रणनीति संभालने के लिए मप्र भाजपा ने नेताओं की सूची तैयार की है। सूत्रों की मानें तो प्रदेश के कई बड़े नेताओं को ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जहां पर गैर भाजपाई सरकार है।

गौरतलब है कि मप्र के नेताओं का दूसरे राज्यों के चुनाव में भी स्ट्राइक रेट हाई रहता है। इसके देखते हुए यहां के नेताओं की मांग अन्य राज्यों में अधिकतर रहती है। इस साल असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं, जिसके लिए अभी से भाजपा के केन्द्रीय संगठन ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। राजनीति के

जानकारों का कहना है कि भले ही इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हों, लेकिन यहां के परिणाम राष्ट्रीय राजनीति में काफी प्रभाव डाल सकते हैं। भाजपा नए राज्यों में अपनी सत्ता लाने की कोशिश में है, तो विपक्ष और कांग्रेस किसी भी स्थिति में भाजपा को सफल नहीं होने देना चाहती है। असम में जहां भाजपा की सरकार है, तो पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन के साथ सरकार चला रही है। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रही है, तो केरल में कांग्रेस को अपनी वापसी की उम्मीद है, जिसे भाजपा रोकना चाहती है।

संगठनात्मक दृष्टि से मप्र बेहतर-जानकारों की मानें तो मप्र संगठनात्मक दृष्टि से बेहतर माना जाता है, ऐसे में यहां के नेताओं को हमेशा ही दूसरे राज्यों के चुनावों की कमान सौंपी जाती है। इस बार भाजपा के लिए सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल मना जा रहा



है। बताया जा रहा है कि यहां के लिए मध्यप्रदेश के तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इनमें सरकार के मंत्रियों के अलावा सांसद, पूर्व सांसद, विधायक व वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। असम राज्य में भी विधानसभा चुनाव होने है, जहां के लिए मध्यप्रदेश भाजपा से 16 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नेताओं को गणतंत्र दिवस के उपरंत दिल्ली बुलाया जाएगा।

जहां उन्हें बताया जाएगा कि असम के किन-किन क्षेत्रों में उन्हें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। सूत्रों का कहना है कि असम में जल्द मध्यप्रदेश में सक्रिय एक वरिष्ठ पदाधिकारी को तैनात कर वहां के संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जबकि उनके स्थान पर किसी दूसरे राज्य के नेता को मध्यप्रदेश भेजा जा सकता है। भाजपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केरल और तमिलनाडु राज्यों में भी भाजपा मध्यप्रदेश के अपने

नेताओं को चुनाव रणनीति संभालने के लिए भेजना चाहती है। लेकिन भाषाई दिक्कतों की वजह से अब तक ऐसे नेता चिन्हित नहीं हो सके हैं, जिन्हें इन राज्यों में भेजा जा सके। कहा जा रहा है कि मध्यप्रदेश से राज्यसभा में भेजे गए केन्द्रीय मंत्री जार्ज कुरियन और डॉ. एल. मुरुगन सहित दूसरे नेताओं को इन राज्यों की कमान सौंपी जा सकती है। जानकारी के अनुसार, निगम-मंडल सहित दूसरे सरकारी पदों पर नियुक्ति मिलने के ठीक बाद भाजपा नेताओं को दूसरे राज्यों की चुनावी कमान सौंप दी जाएगी। पद ग्रहण करने के बाद ये नेता राज्यों में चुनाव होने तक भोपाल या मप्र में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं को अभी से संकेत दिए जा चुके हैं कि उन्हें निगम-मंडल का पद ग्रहण करने के तत्काल बाद अपने दायित्व वाले राज्यों में डेरा जमाना होगा।

4 सी से ज्यादा पूर्णकालिकों की जमावट
जानकारों की मानें तो मध्यप्रदेश में पिछले कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 4 सी से ज्यादा पूर्णकालिकों को इन राज्यों में चुनावी सहयोग के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने संघ से इन पूर्णकालिकों की मांग की है। हालांकि अब तक संघ की ओर से स्वीकृति मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन कहा जा रहा है कि फरवरी के अंत तक ये पूर्णकालिक इन राज्यों में अपनी भूमिका निभाना शुरू कर देंगे। भाजपा से जुड़े सूत्रों की मानें तो इस विषय को लेकर फरवरी के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में भाजपा की एक बैठक होगी। जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सहित दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में ही तय होगी कि मध्य प्रदेश से कौन से नेताओं को चुनावी राज्यों में कमान संभालने के लिए भेजा जाना है।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस संगठन अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं - उमंग सिंघार

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
भोपाल • नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने स्वीकार किया है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस संगठन अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चाहती है कि राज्य में संगठन जल्द पूरी तरह से खड़ा हो जाए, जिससे अगले चुनाव की प्रभावी तरीके से तैयारी की जा सके। गौरतलब है कि कांग्रेस के दिल्ली स्थित मुख्यालय में बुधवार को पार्टी की अहम बैठक होगी, जिसमें मध्य प्रदेश संगठन को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक को लेकर प्रदेश में जहां सियासी बयान शुरू हो गए हैं। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के अलावा राज्य के दूसरे बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस आलाकमान मध्यप्रदेश की राजनीति और संगठन की स्थिति पर लगातार अलर्ट मोड में है। जितनी जल्दी कांग्रेस संगठन मजबूत ढांचे बदलेगा, उतनी ही बेहतर चुनावी तैयारी संभव होगी। सिंघार ने कहा, हम जितनी जल्दी संगठन

बनाएंगे, उतनी ही मजबूती से चुनाव की तैयारी कर पाएंगे। हालांकि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय हैं और जमीन पर काम कर रहे हैं। **लाइव प्रसारण से बचो डरती हैं सरकार**-सिंघार ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा सरकार विधानसभा की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं कराना चाहती। जब देश के छोटे-छोटे राज्य अपनी विधानसभा की कार्यवाही जनता को सीधे दिखा सकते हैं, तो मध्यप्रदेश में किस बात का डर है? भाजपा सरकार की घबराई हुई है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट में उसका असली चेहरा जनता के सामने आ जाएगा। जनता से वोट और सदन में झूट-झूठे दोहरे चरित्र के उजागर होने से ही भाजपा डरती है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कानून/गाइडलाइंस बनाते समय सरकार को सभी वर्गों की राय लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सरकार भू-अर्जन के नाम पर

समितियां बना रही है, जिनमें कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। इससे यह आशंका पैदा होती है कि कानून आम जनता के हित में बनेगा या फिर जमीन लूटने का रास्ता खोलेंगे। सिंघार के बयान पर सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अनुशासनहीनता और गुटबाजी में फंसी हुई है। स्थिति यह है कि कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति ही चुकी है और पार्टी पूरी तरह से अंदरूनी कलह से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने-अपने गुर्गों को आगे बढ़ाने की राजनीति करती रही है। उनके नेता अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में आज एमपी कांग्रेस की एक अहम बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल एमपी कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे।

राहुल बताएंगे संगठन में कैसे काम करना है
संगठन सृजन अभियान के तहत 5 महीने पहले अगस्त में एमपी के सभी 71 संगठनात्मक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी। पांच महीने से जिला अध्यक्ष बिना कार्यकारिणी के ही काम कर रहे हैं। ऐसे में जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी से लेकर संगठन में होने वाली नियुक्तियों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ये बताएंगे कि संगठन में नियुक्ति के बाद किस पदाधिकारी से कैसे काम लेना है और काम की मॉनिटरिंग किस तरह से होगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सीडीब्ल्यूसी मेंबर कमलेश्वर पटेल, सीईसी मेंबर ओंकार सिंह मरकाम, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रान्त भूरिया मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद तीन बजे से होने वाली इस बैठक में मनरेगा का नाम बदले जाने, एसआईआर में वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटाए जाने और एमपी कांग्रेस के संगठन के विस्तार और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।

डांसिंग ट्रैफिक कॉप रणजीत सिंह पर सीपी संतोष सिंह का जीरो टालरेंस डिमोशन कर आरक्षक बनाया

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
इंदौर • इंदौर के डांसिंग ट्रैफिक कॉप के नाम से मशहूर रणजीत सिंह पर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने अनुशासन का डंडा चला दिया है। सीपी सिंह की चल रही जीरो टालरेंस नीति के तहत रणजीत सिंह को डिमोशन कर दिया गया है। अब वह कार्यवाहक प्रधान निकाश शर्मा के अंतर्गत आरक्षक से फिर आरक्षक बना दिए गए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह की ओर से पुलिस उपायुक्त मुख्यालय प्रकाश परिहार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि मार्च 2021 में रणजीत सिंह को आरक्षक से कार्यवाहक प्रधान आरक्षक का उच्च पद दिया गया था। अभी रक्षित केंद्र नगर इंदौर में पदस्थ रणजीत सिंह को दिया गया कार्यवाहक प्रभार निरस्त किया जाता है। उन्हें आरक्षक के मूल पद पर वापस किया जाता है। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि रणजीत पर अभी विभागीय जांच जारी है। शिकायतों और अनुशासनहीनता को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

17 सितंबर को युवती राधिका सिंह ने अपने सोशल अकाउंट पर रणजीत को लेकर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो जारी करते हुए कहा कि - रणजीत ने उससे दोस्ती करने, इंदौर बुलाने और फ्लाइट से टिकट कराने का ऑफर दिया है। उसने इंदौर में ठहरने की व्यवस्था करने की भी बात कही थी। युवती ने कहा कि यह मुझे गलत लगा तो इनकार कर दिया। मुझे उसकी दोस्ती की जरूरत नहीं है। वह अपने हद में रहे। युवती की शिकायत पर सीपी ने कार्रवाई की और इसमें जांच बैठा थी। प्रारंभिक जांच में रणजीत को गलत पाया गया और इसके बाद विभागीय जांच बैठा दी गई। साथ ही फील्ड पोस्टिंग से हटाकर रक्षित केंद्र में अटैच कर दिया। इसके बाद भी रणजीत मान नहीं रहा है और वह लगातार पुलिस वर्दी में रील बना रहा है, जबकि डीजीपी ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हुए हैं। इसके बाद भी लगातार वह रील बना रहा था। इन्होंने हकतों के चलते सीपी ने सख्ती करते हुए डिमोशन के आदेश कर दिए।



मास्टर प्लान की सड़कों में बाधक निर्माण हटाते हुए कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • शहर के सुव्यवस्थित विकास एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुधवार को आयुक्त शक्तिज सिंघल द्वारा शहर में निर्माणाधीन मास्टर प्लान की प्रमुख सड़कों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अभय राजनगावकर, कार्यपालन यंत्री नरेश जायसवाल, ओपी कुशवाह, उपयंत्री पराग अग्रवाल, विशाल सिंह राठौर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आयुक्त सिंघल द्वारा शहर में



मास्टर प्लान अंतर्गत विकसित की जा रही सड़कों-जमजम चौराहा से स्टार चौराहा तक, मूसाखेड़ी चौराहा से सांवरिया धाम मंदिर तक, रिंग रोड खजराना मंदिर द्वार से जमजम चौराहा तक, एडवांस एकेडमी से

रिंग रोड तक, भमोरी चौराहा से एम.आर. 10 तक एवं राजशाही गार्डन से होटल भाव तक, साथ ही सांवर रोड पेट्रोल पंप से शिव शक्ति नगर हनुमान मंदिर तक किए जा रहे सड़क विकास कार्यों का स्थल पर पहुंचकर अवलोकन

किया गया। **बाधाएं प्राथमिकता के आधार पर हटायें**-निरीक्षण के दौरान आयुक्त द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं समय-सीमा की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जहां-जहां निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटायें जाएं। साथ ही सभी कार्यों को तय मानकों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्माण एजेंसियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

बीएलओ एसआईआर को लेकर प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • शासकीय अधिकारी कर्मचारी सयुक्त मोर्चा के बैनर तले बी.एल.ओ.एसआईआर को लेकर हो रही समस्या निराकरण हेतु प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिला। शासकीय अधिकारी कर्मचारी सयुक्त मोर्चा के संरक्षक हरीश बोयत, जिलाध्यक्ष रमेश यादव प्रवीण यादव ने बताया कि विगत कई माह से इंदौर जिले के हजारों कर्मचारी एसआईआर कार्य में कार्यरत हैं वर्तमान में इसे पूर्णता में बीएलओ को फ्रील्ड में आने वाली समस्याओं को लेकर की कार्य पूर्ण होने के बाद भी अपडेट के अभाव



में पुनः नोटिस आने से मतदाताओं द्वारा बीएलओ के साथ अच्छ व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इत्यादि समस्याओं को लेकर अपर कलेक्टर पंवार नवीन विजय से चर्चा कर ज्ञापन सोपा। पंवार ने समस्या निराकरण के लिए

आश्वस्त किया। प्रतिनिधि मंडल में मुख्यरूप से हरीश बोयत, रमेश यादव, अशोक मालवीया, प्रवीण यादव, नीरज जैन, शोलेन्द्र दुबे, अरुण पाण्डेय, रेखा मेहता, दुर्गा कलमे, नेहा गोस्वामी, ज्ञानदेवी शुक्ला, नेहा पडियार आदि साथी उपस्थित थे।

184 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी की आरोपी तीर्थ गोपीकॉन पर मनी लॉड्रिंग का केस

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर • इंडी कंपनी की संपत्तियां तलाशने में जुट गई है। जिससे इस धोखाधड़ी की राशि से जुड़ी संपत्तियों को अटैच किया जा सके। कंपनी पर सीबीआई ने पहले ही धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया हुआ है। इसी आधार पर इंडी ने भी केस अपने हाथ में ले लिया है। जल निगम से 950 करोड़ के ठेके के बदले में तीर्थ गोपीकॉन कंपनी ने विविध बैंक गारंटियां जमा की थीं। जांच में यह गारंटी फर्जी पाई गई थीं। इस पर कंपनी ने इंदौर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और यह गारंटी दूसरे के जरिए बनवाई गई है। मामला हाईकोर्ट जबलपुर गया था। वहां से सीबीआई जांच बैठी और उनके जरिए जांच के

लिए केस दर्ज हुआ था। कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब सीबीआई ने जांच की तो इसमें तीर्थ कंपनी ही दोषी पाई गई थी। पता चला कि इस गोलमाल में तो पूरा नेटवर्क शामिल है। इसके बाद कुम्भानी व अन्य को सितंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। तभी से यह आरोपी जेल में हैं। कंपनी ने इसी बीच स्मार्ट सिटी इंदौर से कुक्कुट केंद्र की जमीन खरीदी का सौदा किया था। यह सबसे महंगा रियल एस्टेट का ये सौदा 454 करोड़ का था। वहां, इसकी किस्त नहीं भरी थी। इसी दौरान घोटाले पर द सूत्र ने बड़ा खुलासा कर दिया था। सबसे पहले हल्द्वर-ह्यश्रबहूह ने ही उजागर किया था कि

सीबीआई की रिपोर्ट में कंपनी ने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट भी फर्जी गारंटी से लिए गए पाए हैं। इंदौर में इस सौदे के लिए उसने करीब 9 करोड़ की बैंक गारंटी दी थी। इस खुलासे के बाद बोर्ड की बैठक हुई और यह सौदा रद्द कर दिया गया था। इंडी ने मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद ग्रुप की संपत्तियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि कंपनी मूल रूप से अहमदाबाद में है। उसके पास अभी इंदौर में संपत्तियां नहीं मिली हैं। उभर जल निगम भी अपनी बैंक गारंटी के 184 करोड़ वसूलने के लिए कंपनियों को संपत्तियां तलाश कर रहा है। इसके लिए इंदौर जिला प्रशासन, पंजीयन विभाग और अन्य विभागों को पत्र भेजा

है। इस मामले में सीबीआई ने कुम्भानी, राहुल गुप्ता के साथ ही फिरोज खान, गोविंद चंद्र हंसदा, गौरव धाकड़ और तीर्थ गोपीकॉन कंपनी को आरोपी बनाया है। इनके खिलाफ धारा 420, 467, 468 व 471 में केस किया गया है। इसी एफआईआर को इंडी ने लिया और मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में सीबीआई जांच में सामने आया था कि तीर्थ गोपीकॉन कंपनी, बैंक मैनेजर के साथ मिलकर सांठगांठ से यह फर्जी बैंक गारंटी हासिल कर रही है। कंपनी मूल रूप से अहमदाबाद (गुजरात) की है। मध्यप्रदेश में इसका ऑफिस इंदौर में 204, अमर मेट्रो पगानिस पाना इंदौर में है। कंपनी का एमडी महेश भाई कुम्भानी है। इसमें प्रमोटर व डायरेक्टर चंद्रिकाबेन कुम्भानी

तीन कामों की ये गारंटी जांच में

इंडी ने इस केस में कुल आठ बैंक गारंटियों की जांच की जा रही है। गारोली डेम छतरपुर केस में 39.20 करोड़ की कुल तीन बैंक गारंटी दी गई हैं। इसमें दो 9.80-9.80 करोड़ की और एक 19.60 करोड़ की थी। सागर के मडिया डेम के लिए तीन बैंक गारंटी 32.40 करोड़ की दी थी। इसमें एक 16.20 करोड़ और बाकी दो 8.10-8.10 करोड़ की थी। वहीं दो बैंक गारंटी डिंडोरी के काम के लिए कुल 111.61 करोड़ (50 करोड़ व 61.61 करोड़) की थीं वही दो थीं। यह सभी बैंक गारंटी 184 करोड़ की थी, जो फर्जी पाई गई थी। इन सभी की जांच की जा रही है।

और नान एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर पल्लव कुम्भानी हैं। कंपनी मूल रूप से सरकार के सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के टेंडर लेती है। इसने इंदौर, उज्जैन और छतरपुर जैसे शहरों में कई प्रोजेक्ट किए हैं। इंदौर में नगर निगम और स्मार्ट सिटी के तहत सफाया प्रोजेक्ट, नाला टैपिंग, एसटीपी प्रोजेक्ट, सरवट प्रोजेक्ट जैसे कई प्रोजेक्ट किए हैं। इनमें उज्जैन का अमृत

2.0 प्रोजेक्ट भी शामिल है। कंपनी का यह पूरा दोतरफा खेल है। कंपनी बैंक से सांठगांठ कर फर्जी बैंक गारंटी बनवाती है। इसके बाद काम शुरू कर सरकार से भुगतान लेना शुरू कर देती है। जैसे कि जल निगम के 950 करोड़ के ठेके में कंपनी ने 84 करोड़ का भुगतान भी ले लिया। कंपनी हर जगह इसी तरह का खेल करती रही है।